



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]
No. 67]नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2010/फाल्गुन 7, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2010/PHALGUNA 7, 1931

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सं. एफ. 2(12)-बॉ(डी)/2010.—निम्नलिखित को
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

‘बजट 2010-2011

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण

26 फरवरी, 2010

अध्यक्ष महोदया,

मैं वर्ष 2010-11 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

मैंने 2009 में, जब इस महान सदन में फरवरी में अन्तरिम बजट और जुलाई में नियमित बजट प्रस्तुत किया था तो भारतीय अर्थव्यवस्था भारी अनिश्चितताओं से जूझ रही थी। विकास की गति धीमी होनी शुरू हो गई थी और कारोबारी माहौल मंद था। विकसित देशों में व्यापक आर्थिक मंदी के चलते, उच्च वृद्धि को बनाए रखने की अर्थव्यवस्था की क्षमता पर गम्भीर आंच आने लगी थी।

2. हमें, तथा अनेक अन्य देशों के नीति निर्माताओं को यह स्पष्ट नहीं था कि इस संकट से आखिरकार कैसे पार पाया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास-गति पर इसका क्या प्रभाव होगा? कितनी जल्दी हम अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में समर्थ होंगे? वैश्विक अर्थव्यवस्था का यह अल्पावधिक परिदृश्य निराशाजनक था और इस बात पर आम सहमति थी कि वर्ष 2009 में सम्पूर्ण विश्व इस संकट की मार झेलता रहेगा।

3. हमारे देश में, दक्षिण-पश्चिम मानसून के देशी से और सामान्य से कम आने के कारण यह अनिश्चितता और बढ़ गई थी। इससे देश में खरीफ की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। खाद्यान्नों के उत्पादन और खाद्य पदार्थों की कीमतों तथा ग्रामीण मांग की वृद्धि पर इनके संभावित प्रतिकूल प्रभावों के बारे में चिन्ताएं होने लगी थीं।

4. आज, जब मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमने इन संकटों का अच्छी तरह सामना किया है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था, एक वर्ष पहले की स्थिति के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आज चुनौतियां, जै महीने पहले जब श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार वापस सत्ता में आयी थी और प्रधानमंत्री डा. मनोहरन सिंह ने दूसरी बार सरकार का गठन किया था, के मुकाबले कम हैं।

5. अपने पिछले बजट भाषण में मैंने जिन तीन चुनौतियों और मध्यावधिक परिप्रेक्ष्य का जिक्र किया था, वे आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। ये अगले कुछ वर्ष तक भारतीय नीति-निर्धारकों के लिए दिशा-निर्देशों का काम करते रहेंगे।

6. हमारे सामने पहली चुनौती, 9 प्रतिशत के उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के रस्ते पर तेजी से लौटने और फिर ‘दोहरे अंक के वृद्धि अवरोध’ को पार करने हेतु साधनों को पाने की है। इसके लिए विगत कुछ महीनों में देखी गई वृद्धि में प्रभावशाली सुधार को नई गति प्रदान करने की आवश्यकता है। आगामी महीनों में, सुधार की इस प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाने के इस प्रयास में, मैं इन देव की सहायता का आह्वान करता हूँ।

7. विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना करने और बनने की वह हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। अतः दूसरी चुनौती विकास को

अधिक समावेशी बनाने में हालिया उपलब्धियों के समेकन हेतु आर्थिक वृद्धि को सही ढग से काम में लाने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को और बढ़ाना होगा जिससे एक निश्चित समय-सीमा में वांछित उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।

8. हमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना होगा, शिक्षा के अवसर बढ़ाने होंगे और परिवार स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता है और हमें ये संसाधन ढूँढ़ने होंगे।

9. तीसरी चुनौती, प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, संरचनाओं और संस्थाओं में कमजोरियों से सम्बन्धित है। वास्तव में, आने वाले वर्षों में, यदि कोई कारक हमें एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में हमारी क्षमता को साकार करने में बाधक हो सकता है तो वह हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणालियों की अड़चन है। इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर अनेक पहल की गई हैं। उनमें से कुछ उन क्षेत्रों में सरकारी कामकाज के तौर-तरीकों में सुधार लाने में कारगर रहे हैं। परन्तु इस मोर्चे पर कामयाबी की संतुष्टि होने से पूर्व हमें बहुत कुछ करना बाकी है।

10. केन्द्रीय बजट सरकारी लेखा-जोखा की महज एक घोषणा नहीं हो सकती है। इसमें सरकार की दूरवृष्टि और भावी नीतियां परिलक्षित होती हैं।

11. विकास और आर्थिक सुधारों के चलते, आर्थिक क्रियाकलापों का केन्द्र बिन्दु अब गैर-सरकारी संगठनों की ओर हो गया है। इससे एक सामर्थ्यकारी के रूप में सरकार की भूमिका पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाने लगा है।

12. एक समर्थ सरकार अपने नागरिकों की जरूरत की प्रत्येक चीज सीधे तौर पर वितरित करने का प्रयास नहीं करती है। वास्तव में यह एक ऐसी सशक्त व्यवस्था तैयार करती है जिससे वैयक्तिक उद्यमशीलता और सृजनशीलता फले-फूले। सरकार समाज के लाभ-वांचित वर्गों की मदद करने और सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करती है।

13. बजट की यही आम अवधारणा आज मेरे भाषण का आधार है। मैं अब अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त सिंहावलोकन प्रस्तुत करके आरंभ करूँगा।

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

14. कल, मैंने सभा-पटल पर आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की थी। इसमें पिछले बाहर महीनों के दौरान देश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। मैं केवल कुछ प्रमुख बातें बताना चाहता हूँ जो इस बजट की पृष्ठभूमि बनी हैं।

15. वित्त वर्ष 2009-10 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। 2008-09 की दूसरी छमाही में उल्लेखनीय गिरावट से, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, पिछले तीन वर्षों में 9 प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि से गिरकर 6.7 प्रतिशत हो गई थी। हम विश्व के पहले कुछ देशों में थे जिन्होंने वैश्विक मंदी के नकारात्मक परिणामों से निपटने के लिए व्यापक नीतिगत पैकेज पर अमल किया। इसमें उदार मौद्रिक नीतिगत सहायता के साथ-साथ प्रचुर राजकोषीय विस्तार शामिल था।

16. इन नीतिगत उपायों की कारणता त्वरित सुधार से सप्तष्ट हुई है। अर्थव्यवस्था में 2009-10 की पहली तिमाही में ही स्थिरता आने लगी थी, जब इसने गत वर्ष की चौथी तिमाही में दर्ज की गयी 5.8 प्रतिशत की तुलना में 6.1 प्रतिशत की स.घ.उ. वृद्धि दर्ज की थी। दूसरी तिमाही में इसमें बहुत भजबूती आई और वृद्धि दर बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गई। अग्रिम अनुमानों में 2009-10 की सम्भावित वृद्धि 7.2 प्रतिशत आंकी गई है। इससे वास्तव में, हमारा नीतिगत दृष्टिकोण सही साबित हुआ है। 2009-10 की तीसरी और चौथी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों के उपलब्ध होने पर अंतिम आंकड़े इससे भी बेहतर हो सकते हैं।

17. यह बहली बहुत उत्साहवर्धक है क्योंकि यह कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि के बावजूद हासिल हुई है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विनिर्माण क्षेत्र में फिर से आई तेजी का परिणाम है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में इस सेक्टर के उदय का द्योतक है। दिसम्बर, 2009 में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 18.5 प्रतिशत रही। यह विगत दो दशकों में सर्वाधिक है। पण्य नियांतों में भी, लगातार लगभग बारह माह की गिरावट के बाद, नवम्बर और दिसम्बर, 2009 में सकारात्मक वृद्धि के चलते बदलाव के संकेत हैं। जनवरी के नियांत संबंधी आंकड़े उत्साहवर्धक हैं। आशा है कि भारी मात्रा में निजी निवेश अब 9 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि बनाए रखने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। मुझे आशा है कि कुछ भाग का साथ मिलने पर निकट भविष्य में 10 प्रतिशत का आंकड़ा पार किया जा सकता है।

18. वर्ष 2009-10 की दूसरी छमाही के दौरान एक प्रमुख चिन्ता दो अंकों में खाद्य मुद्रास्फीति का होना रहा है। 2008 में वित्तीय संकट से पूर्व वस्तुओं के मूल्य में आई वैश्विक तेजी के समय से खाद्य मूल्यों में बढ़ोत्तरी होने लगी थी, परन्तु यह आशा थी कि जून, 2009 से आरंभ होने वाले कृषि मौसम से खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। तथापि, देश के बड़े भू-भाग में अनिश्चित मानसून और सूखे जैसी स्थितियों से कुछ अनिवार्य वस्तुओं की आर्थिक आपूर्ति संबंधी अड़चनें पैदा हो गईं। इससे मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाएं व्याप्त हो गईं। दिसम्बर, 2009 से ऐसे संकेत मिले हैं कि ईंधन उत्पादों के मूल्यों में ब्रह्मिक बढ़ोत्तरी के साथ-साथ खाद्य पदार्थों के इन उच्च मूल्यों का असर अन्य खाद्य-भिन्न वस्तुओं के मूल्यों में बढ़त के रूप में हो रहा है। जनवरी के मुद्रास्फीति के आंकड़े इस रुक्षान की पुष्टि करते जान पड़ते हैं।

19. सरकार इस स्थिति के प्रति पूरी तरह सचेत है और उसने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सलाह मंशविर से अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों से अगले कुछ महीनों में मुद्रास्फीति नीचे आ सकेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि देश में खाद्य सुरक्षा का बेहतर प्रबन्धन है।

विकास का सुदृढ़ीकरण

20. एक जटिल अर्थव्यवस्था का प्रबंधन एक कठिन कार्य है, विशेषकर तब जब यह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में एक विकासशील अर्थव्यवस्था है फिर भी हमें उपाय तलाशने होंगे और इन उपायों को सही समय पर करना होगा।

21. वैश्विक मंदी के प्रभावों से सफलतापूर्वक उबरने के बाद, हमें विकास में पुनः आई तेजी को आगे बढ़ाने और मध्यावधि में इसे बनाए रखने हेतु देश के वृहत् आर्थिक वातावरण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हमें अर्थव्यवस्था को प्रदान किए गए प्रोत्साहन उपायों की समीक्षा करने और संकट पूर्व के पांच वर्ष की अवधि में पर्याप्त वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाले राजकोषीय समेकन के तरजीही रास्ते पर बढ़ने की आवश्यकता है। हमें विकास के आधार को अधिक व्यापक बनाने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपूर्ति-मांग असंतुलनों का प्रबन्धन बेहतर ढंग से हो।

राजकोषीय समेकन

22. घरेलू मांग को बढ़ाने में वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की सफलता का पता इसकी संरचना से लगाया जा सकता है। सरकार का दृष्टिकोण अप्रत्यक्ष करने में कटौतियाँ करके और भवात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम तथा ग्रामीण अवसंरचना जैसे कार्यक्रमों पर सरकारी व्यय बढ़ा कर लोगों के हाथों में खर्च योग्य आमदनी बढ़ाने का था। अब, जबकि स्थिति में सुधार होने लगा है, सरकारी खर्चों की समीक्षा करने, संसाधन जुटाने और उन्हें अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाने में लगाने की आवश्यकता है।

23. वर्ष 2010-11 की राजकोषीय नीति बनाने में, मैंने तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्य किया है। इसने पिछले दो वर्षों के प्रोत्साहनकारी राजकोषीय दृष्टिकोण से संतुलित निकासी की नीति की सिफारिश की है। आयोग ने 2014-15 तक केन्द्र और राज्यों के कुल ऋण की अधिकतम सीमा, सकल घरेलू उत्पाद के 68 प्रतिशत पर करने की सिफारिश की है।

24. राजकोषीय समेकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, यह पहली बार होगा कि सरकार घरेलू सरकारी ऋण-स.घ.उ. अनुपात में एक सुस्पष्ट कटौती का लक्ष्य तय करेगी। मेरा छह माह के भीतर एक प्राप्तिथित पत्र लाने का इशारा है। इसमें स्थिति का विस्तृत विश्लेषण और समग्र सरकारी ऋण को कम करने का खाका दिया जाएगा। इसके बाद, इस विषय पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

कर सुधार

25. मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि एक सरल कर प्रणाली बनाने की प्रक्रिया अब पूरी होने को है। इस प्रणाली में अपवाद न्यूनतम होंगे और स्वैच्छिक कर अनुपालन संवर्धित करने के उद्देश्य से निम्न दर्दे होंगी। प्रत्यक्ष कर संहिता के संबंध में हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि सरकार 1 अप्रैल, 2011 से प्रत्यक्ष कर संहिता को लागू करने की स्थिति में होंगी।

26. वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में, हम इसकी संरचना पर एक व्यापक सहमति बनाने पर ध्यान केन्द्रित करते रहे हैं। नवम्बर, 2009 में, राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने वस्तु एवं सेवा कर संबंधी पहला परिचर्चा पत्र आम जनता की जानकारी के लिए प्रदत्त किया। तेरहवें वित्त आयोग ने भी वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशों की हैं, जिनसे इस बारे में चल रहे विचार-विमर्शों में सहायता मिलेगी। हम वस्तु एवं सेवा कर की संरचना तथा इसके शीघ्र कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अनिम रूप देने के लिए सशक्त समिति के साथ सक्रियतापूर्वक जुटे हैं। मेरा पूर्ण

प्रयास होगा कि अप्रैल, 2011 में प्रत्यक्ष कर संहिता के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा कर को लागू कर दिया जाए।

पब्लिक सेक्टर उपक्रमों का लोक स्वामित्व

27. 2009-10 का बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की सम्पत्ति और समृद्धि में भागीदारी के लिए सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए जनता को आमन्त्रित किया था।

28. उसके बाद, आइल इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी, एनटीपीसी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में स्वामित्व को व्यापक आधार प्रदान किया गया है जबकि राष्ट्रीय खानिज विकास निगम और सतलुज जल विद्युत निगम में यह प्रक्रिया चल रही है। सरकार मौजूदा वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। इस प्रक्रिया के जरिए, मेरा 2010-11 के दौरान इससे अधिक राशि जुटाने का प्रस्ताव है। इन प्राप्तियों का उपयोग नई आस्तियां सृजित करने हेतु सामाजिक क्षेत्र की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा।

29. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के सूचीयन से, सभी हितधरकों, सरकार, कम्पनी और शेयरधारकों के हितों में बढ़ोतारी की संभावना के अतिरिक्त, कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार होता है। अक्तूबर, 2004 के बाद से सूचीबद्ध पांच कम्पनियों का बाजार पूंजीकरण, अंकित मूल्य 78,841 करोड़ रुपये से 3.8 गुणा बढ़कर 2,98,929 करोड़ रुपये हो गया है।

30. सरकारी व्यय को सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप लाकर, इसका प्रभावी प्रबन्धन राजकोषीय समेकन प्रक्रिया का भाग है। इसके लिए सब्सिडियों को समुचित रूप से लक्षित करने और व्यय समायोजन की आवश्यकता है।

उर्वरक सब्सिडी

31. मैंने 2009 के अपने बजट भाषण में उर्वरक सेक्टर के लिए सरकार के आशय की घोषणा की थी। सरकार द्वारा तदन्तर, उर्वरक सेक्टर के लिए एक घोषणा आधारित सब्सिडी नीति मंजूर की गई है और यह 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगी। आशा है कि इस नीति से नए पुष्ट उत्पादों के जरिए संतुलित उर्वरक प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और इस नीति का फोकस उर्वरक उद्योग द्वारा विस्तार सेवाओं पर होगा। इससे कृषि उत्पादकता में बढ़ोतारी होगी और परिणामस्वरूप किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। इस नीति के लागू होने से सब्सिडी बिल में कमी होने के अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी की मांग की अस्थिरता में कमी आएगी। सरकार इस बात को सुनिश्चय करेगी कि संक्रमण वर्ष 2010-11 में पोषक आधारित उर्वरक मूल्य इस समय मौजूद अधिकतम खुदरा मूल्यों के आसपास बने रहें। इस नई प्रणाली से किसानों को सीधे सब्सिडियां देने का मार्ग प्रशस्त होगा।

पेट्रोलियम और डीजल मूल्य-निर्धारण नीति

32. पिछले बजट में, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की व्यवहार्य तथा टिकाऊ प्रणाली पर सरकार को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करने की घोषणा की गयी थी। श्री किरिट पारीख की अध्यक्षता में गठित समूह ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों पर निर्णय मेरे सहयोगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा यथा समय लिया जाएगा।

33. मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि हमने पिछले वर्ष के बजट दस्तावेजों के भाग के रूप में न केवल राजकोषीय रोडमैप का पालन किया, बल्कि इसमें सुधार भी किए। वर्ष 2008-09 की देयताओं की पूर्ति करने के सिवाय, हमने तेल अथवा उर्वरक बांड जारी नहीं किए। जब मैं कुछ समय बाद बजट अनुमानों का उल्लेख करूँगा, तब मैं इन बांडों की संख्या बताऊंगा।

निवेश माहौल में सुधार

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

34. इस वर्ष, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अन्तर्राष्ट्रीय वैश्वक पूँजी प्रवाहों में गिरावट के बावजूद सतत बना रहा। भारत में अप्रैल-दिसंबर, 2009 के दौरान 20.9 बिलियन अमरीकी डालर का एफडीआई इक्विटी अन्तर्राष्ट्रीय प्राप्त हुआ जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 21.1 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुआ था।

35. सरकार ने एफडीआई व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि यह विदेशी निवेशकों की समझ में आसानी से आ जाए। यहली बार, स्वामित्व तथा नियंत्रण को एफडीआई नीति के मुख्य भाग के रूप में मान्यता प्रदान की गयी तथा भारतीय कम्पनियों में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आकलन की पद्धति को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया। डाउनस्ट्रीम निवेश सम्बन्धी एक ठेस नीति भी तैयार की गयी है। मूल्य निर्धारण और प्रौद्योगिकी अन्तरण शुल्क, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम का भुगतान एवं रॉयलटी भुगतानों के पूर्णतः उदारीकरण संबंधी एक अन्य पहल रही है। इन भुगतानों को अब स्वतः अनुमोदित मार्ग के अन्तर्गत किया जा सकता है।

36. सरकार की मंशा एफडीआई नीति को, पहले के सभी विनियमों तथा दिशानिर्देशों को एक व्यापक दस्तावेज में समेकित करके, प्रयोक्ता अनुकूल भी बनाना है। इससे विदेशी निवेशकों के लिए हमारी एफडीआई नीति की सुस्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता बढ़ जाएगी।

वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद्

37. वर्ष 2008-09 के वित्तीय संकट से सम्पूर्ण विश्व में बैंकिंग तथा वित्तीय बाजारों की संरचना में मूलभूत अन्तर आया। वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के तंत्र को सुदृढ़ बनाने तथा सांस्थानिक रूप देने की दृष्टि से, सरकार ने एक शीर्ष स्तरीय वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया है। विनियामकों की स्वायत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह परिषद् बड़े पैमाने पर वित्तीय एकीकरण की कार्यप्रणाली सहित अर्थव्यवस्था के बृहद् विवेकसम्मत पर्यवेक्षण को मॉनीटर करेगी और अन्तर-विनियामक समन्वय सम्बन्धी मुद्दों का समाधान करेगी। यह परिषद् वित्तीय बोधगम्यता तथा वित्तीय समावेशन पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करेगी।

बैंकिंग लाइसेंस

38. भारतीय बैंकिंग प्रणाली इस संकट से अछूती रही। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बैंकिंग प्रणाली आकार तथा सुविज्ञता में आगे बढ़े ताकि आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इसके अतिरिक्त, बैंकों के भौगोलिक क्षेत्रों

विस्तार देने तथा बैंकिंग सेवाओं की पहुँच में सुधार करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के भागीदारों को कुछ अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार कर रहा है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे भारतीय रिजर्व बैंक के पात्रता मानदण्डों की पूर्ति करें।

पब्लिक सेक्टर बैंकों का पूँजीकरण

39. वर्ष 2008-09 के दौरान, सरकार ने चार पब्लिक सेक्टर बैंकों में पूँजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात का बहनीय स्तर बनाए रखने के लिए, टियर-I कैपिटल के बतौर 1900 करोड़ रुपए डाले। 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अब डाली जा रही है। वर्ष 2010-11 के लिए मैं 16,500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक 31 मार्च, 2011 तक न्यूनतम 8 प्रतिशत टियर-I कैपिटल प्राप्त कर सकें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पूँजीकरण

40. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन बैंकों की पूँजी की साझीदारी केन्द्र सरकार, प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इन बैंकों का अन्तिम पूँजीकरण 2006-07 में हुआ था। मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने हेतु और पूँजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि उनके पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वर्धित ऋण प्रदान करने हेतु पर्याप्त पूँजी आधार हो।

कारपोरेट गवर्नेंस

41. देश में कारपोरेट गवर्नेंस तथा विनियम में सुधार, समग्र निवेश माहौल बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने संसद में कम्पनी विधेयक, 2009 प्रस्तुत किया है। यह मौजूदा कम्पनी अधिनियम, 1956 का स्थान लेगा। यह प्रस्तावित नया विधेयक बदलते कारोबारी माहौल के परिप्रेक्ष्य में कारपोरेट क्षेत्र में विनियम से सम्बद्ध मुद्दों का समाधान करेगा।

निर्यात

42. सरकार ने कतिपय क्षेत्रों में निर्यात हेतु 31 मार्च, 2010 तक लदान-पूर्व निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। मैं इस 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता को एक वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा, तथा लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

43. विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने बड़ी मात्रा में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित किया है। 2009-10 की पहली तीन तिमाहियों में, सेज से प्राप्त निर्यात ने, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, 127 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सरकार सेज का निरन्तर विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि निवेश आकृष्ट हो और निर्यात एवं रोजगार को बढ़ावा मिले।

कृषि विकास

44. कृषि क्षेत्र समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने, ग्रामीण आय को बढ़ाने तथा खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के हमारे संकल्प का

केन्द्र बिन्दु है। इस क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाने हेतु, सरकार का इरादा चतुर्थ स्तरीय कार्ययोजना का अनुसरण करने का है जिसमें (क) कृषि उत्पादन; (ख) उत्पाद की बबंदी में कमी; (ग) किसानों को ऋण सहायता; और (घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर जोर देना शामिल हैं।

45. कार्ययोजना का पहला घटक, ग्राम सभाओं तथा किसान परिवारों के सक्रिय सहयोग से, हरित क्रान्ति का विस्तार देश के पूर्वी क्षेत्र में करना है जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा शामिल हैं। वर्ष 2010-11 के लिए, मैं इस पहल हेतु 400 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं।

46. गणतंत्र के 60वें वर्ष में, 2010-11 के दौरान वर्षाधारित क्षेत्रों में 60,000 "दलहन और तेल बीज ग्रामों" को आयोजित करने और जल संचयन, जल संधर प्रबन्धन तथा मूदा स्थिति के लिए एकीकृत तंत्र की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ताकि शुष्क भू-कृषि क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। मैं इस प्रयोजनार्थ 300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। यह प्रोत्साहन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक अभिन्न भाग होगा।

47. संरक्षित कृषि जिसमें मूदा स्थिति, जल संरक्षण तथा जैव-विविधता के परिरक्षण में एक साथ ध्यान देना शामिल है, के माध्यम से हरित क्रान्ति वाले क्षेत्रों में पहले से प्राप्त लाभों को कायम रखा जाएगा। मैं इस जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु 200 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं।

48. कार्ययोजना का दूसरा घटक, देश में भण्डारण में बड़ी मात्रा में बबंदी को कम से कम करने तथा मौजूदा खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं के प्रचालन से सम्बद्ध है। इसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने हाल में कहा है "हमें बेहतर प्रतिस्फूर्ति की आवश्यकता है और इसलिए खुदरा व्यापार को खोलने के लिए ठोस दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है।" इससे खेत स्तरीय कीमतों, थोक मूल्य कीमतों तथा खुदरा कीमतों के बीच व्याप्त भारी अन्तर को पाटने में सहायता मिलेगी।

49. भारतीय खाद्य निगम के पास भण्डारण क्षमता की भारी कमी के कारण बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खारीदे गए अनाज की बबंदी होती है। भण्डारण क्षमता में यह घाटा निजी क्षेत्र की भागीदारी से मौजूद योजना के जरिए पूरा किया जाता है जहाँ भारतीय खाद्य निगम प्राइवेट पार्टियों से 5 वर्ष की गारंटी अवधि हेतु गोदाम किए गए पर लेता रहा है। इस अवधि को अब बढ़ाकर 7 वर्ष किया जा रहा है।

50. कार्ययोजना का तीसरा घटक किसानों की ऋण उपलब्धता में सुधार करने से सम्बद्ध है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि बैंक पिछले कुछ वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को लगातार पूरा करते रहे हैं। वर्ष 2010-11 हेतु, यह लक्ष्य मौजूदा वर्ष में 3,25,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,75,000 करोड़ रुपए किया गया है।

51. "किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना" सं.प्र.ग्र. सरकार की एक मुख्य पहल थी। देश के कुछ राज्यों में हाल

के सूखे और कुछ अन्य राज्यों में आयी भयंकर बाढ़ को देखते हुए, मैं किसानों द्वारा लिए गए ऋण की बापती अदायगी अवधि को 31 दिसंबर, 2009 से 30 जून, 2010 तक छह माह बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

52. पिछले बजट में, मैंने अत्यावधि फसल ऋणों की समय अनुसूची के अनुसार अदायगी करने वाले किसानों हेतु प्रोत्साहन स्वरूप 1 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज आर्थिक सहायता मुहैया करायी थी। मैं 2010-11 में इस आर्थिक सहायता को फसल ऋणों की समय पर अदायगी करने वाले किसानों हेतु 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रकार, ऐसे किसानों हेतु व्याज की प्रभावी दर प्रति वर्ष 5 प्रतिशत होगी। बजट में इस विषय में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है।

53. कार्ययोजना के चौथे घटक का उद्देश्य अत्याधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करना है। पहले से स्थापित दस मेंगा फूड पार्क परियोजनाओं के अतिरिक्त, सरकार ने ऐसे पांच और पार्कों की स्थापना का निर्णय लिया है।

54. बाजार योजना के लिए कृषि के भाग के रूप में, विदेशी वाणिज्यिक उधार अब से कोल्ड स्टोरेज अथवा कोल्ड रूम सुविधा हेतु उपलब्ध होंगे जिनमें कृषि एवं सम्बद्ध उत्पादों, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु फार्म लेवल प्री-कूलिंग शामिल होगा। इसीबी नीति के अन्तर्गत आधारभूत संरचना की परिभाषा में परिवर्तन किए जा रहे हैं।

आधारभूत संरचना

55. आर्थिक विकास को बनाए रखने हेतु सड़कों, बंदरगाहों, हवाई-अड्डों तथा रेलवे जैसे उच्च गुणवत्ता वाले वास्तविक आधारभूत संरचना का त्वरित विकास अत्यावश्यक है। इस क्षेत्र में नीतिगत अन्तरालों का समाधान करते समय, मैं ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के उन्नयन पर यथावत जोर देने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 2010-11 के बजट में, मैंने देश में आधारभूत संरचना के विकास हेतु 1,73,552 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जो कुल आयोजना आबंटन का 46 प्रतिशत से अधिक है।

56. सड़क क्षेत्र में स्पष्ट सुधार दिखाई दे, इस हेतु सरकार ने प्रतिदिन 20 कि.मी. की गति से राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के निर्माण का लक्ष्य रखा है। कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु, नीतिगत ढांचे में, विशेष रूप से सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए कार्यान्वयन की जा रही परियोजनाओं के सम्बन्ध में, परिवर्तन किए गए हैं। वर्ष 2010-11 हेतु, मैं सड़क परिवहन हेतु इस आबंटन को 17,520 करोड़ रुपए से 13 प्रतिशत तक अधिक बढ़ाकर 19,894 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

57. माननीय सदस्य रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण एवं विस्तारण हेतु अपेक्षित बड़ी मात्रा में निवेश के सम्बन्ध में रेलमंत्री के विचारों से पहले से अवगत हैं। मैंने बजट 2010-11 में रेलवे की सहायता हेतु 16,752 करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष रेलवे के लिए बजटीय सहायता में पर्याप्त बढ़ोत्तरी की गयी थी। यह उसकी अपेक्षा लगभग 950 करोड़ रुपए अधिक है।

58. समर्पित फ्रेट कॉरिडोर को अनुपूरक करने हेतु, दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक मार्ग परियोजना एकीकृत क्षेत्रीय विकास के लिए शुरू की गयी है। पारिस्थितिकी-अनुकूल विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना वाले छह औद्योगिक निवेश केन्द्रों (नोड्स) के सूजन का प्रारंभिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड

59. सरकार ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना की है। इसका संवितरण मार्च, 2010 की समाप्ति तक 9,000 करोड़ रुपए तक और मार्च, 2011 तक 20,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने की आशा है। इस कम्पनी को आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाओं को बैंक ऋण से वित्तपोषित करने हेतु भी प्राधिकृत किया गया है। इसने भौजूदा वर्ष के दौरान 3,000 करोड़ रुपए का पुनर्वित्तपोषण किया तथा इस राशि के 2010-11 में दुगुनी से अधिक होने की आशा है। पिछले बजट में घोषित वित्तपोषण प्राप्त करने की योजना से यह आशा है कि प्रारम्भ में, इससे आगामी तीन वर्षों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के वित्तपोषण की व्यवस्था होगी।

ऊर्जा

60. सरकार विद्युत क्षेत्र में क्षमता वर्धन को उच्च प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की उच्च क्षमता वाले विद्युत संयंत्रों में अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी को शामिल करने सम्बन्धी ढांचा अब प्रभावी है। मेंगा पावर पालिसी को संशोधित किया गया है और अब यह राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 तथा टैरिफ नीति, 2006 के अनुरूप है। इससे वितरण इकाइयों द्वारा उत्पादन लागत तथा खरीद की गयी विद्युत लागत को कम करने में मदद मिलेगी। मैंने विद्युत क्षेत्र हेतु आयोजना आवंटन को, 2009-10 में किए गए 2,230 करोड़ रुपए से बढ़ाकर, 2010-11 में 5,130 करोड़ रुपए करते हुए दुगुने से अधिक कर दिया है। इसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जो भारत निर्माण का एक भाग है, के लिए आवंटन शामिल नहीं है।

61. कोयला भारतीय ऊर्जा क्षेत्र का मुख्य आधार है और वर्तमान में 75 प्रतिशत विद्युत उत्पादन कोयला आधारित है। केप्टिव माइनिंग हेतु कोयला ब्लाकों का आवंटन करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आरम्भ करने का प्रस्ताव है ताकि इन ब्लाकों से उत्पादन में बेहतर पारदर्शिता और वर्धित भागीदारी सुनिश्चित हो।

62. कोयला क्षेत्र में एक समान व्यवस्था के निर्माण हेतु “कोयला विनियामक प्राधिकरण” की स्थापना करने के लिए, सरकार कदम उठाना चाहती है। इससे कोयले के किफायती मूल्य निर्धारण और निष्पादन मानक की बैंचमार्किंग जैसे मुद्दों का समाधान करने में आसानी होगी।

63. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन में भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने की बात कही गयी है। इस मिशन के तहत, वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हेतु योजना परिव्यय को 61 प्रतिशत बढ़ाकर, 2009-10 में किए गए 620 करोड़ रुपए से 2010-11 में 1,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

64. जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र की जलवायु अधिक प्रतिकूल है और यह क्षेत्र ऊर्जा कमी से ग्रस्त है। इस समस्या के समाधान हेतु, लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से सौर, लघु जल, एवं माइक्रो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन

65. नकारात्मक पर्यावरणीय परिणामों तथा औद्योगिकरण और शहरीकरण से सम्बद्ध वर्धित प्रदूषण स्तरों में सुधार करने के लिए, मैं बजट 2010-11 में कई सकारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव करता हूँ।
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)

66. देश में कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तरों तक पहुंच गया है। जहां एक ओर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि “प्रदूषक के कीमत चुकाने” का सिद्धांत प्रदूषण प्रबन्धन का मूल दिशानिर्देश मानदण्ड बना रहे, वहीं हमें स्वच्छ ऊर्जा के विकास पर सकारात्मक जोर भी देना होगा। मैं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान तथा अभिनव परियोजनाओं के निधिपोषण हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इसके निधिपोषण की विधि को अपने भाषण के भाग खं में रेखांकित करूँगा।

बहिःस्वाव शोधन संयंत्र, तिरुपुर

67. तिरुपुर, तमिलनाडु में स्थित टेक्स्टाइल निटवियर क्लस्टर देश के हॉजरी निर्यात में मुख्य योगदानकर्ता है। मैं तमिलनाडु सरकार को तिरुपुर में इस उद्योग को बनाए रखने हेतु जीरो लिकिवड डिस्चार्ज प्रणाली के स्थापन की लागत हेतु एकबारी 200 करोड़ रुपए का अनुदानउपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ। यह उद्योग, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है।

गोवा के लिए विशेष स्वर्ण जयंती पैकेज

68. मैं गोवा के लिए विशेष स्वर्ण जयंती पैकेज के बतौर 200 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को इसके बीचों, जिनके कटाव की संभावना है, का पुनरुद्धार कर और सतत वानिकी के जरिए इसका हरित क्षेत्र बढ़ाकर प्राकृतिक संसाधनों को परिरक्षित करेगा।

राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण (एनजीआरबीए)

69. “मिशन स्वच्छ गंगा 2020” का यह उद्देश्य है कि नगर निगम का शोधित न किया गया कोई भी मलव्ययन अथवा औद्योगिक बहिःस्वाव राष्ट्रीय नदी में नहीं बहाया जाएगा। यह मिशन पहले आरम्भ किया जा चुका है। मैं इस प्राधिकरण के लिए वर्ष 2010-11 का आवंटन दुगुना कर 500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

70. मुझे मानवीय सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और नाडिया जिले के कुछ भागों में भागीरथी नदी और गंगा-पद्मा नदी के तटबंध संरक्षण निर्माण कार्य योजनाएं केन्द्र द्वारा प्रायोजित बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल की गयी हैं। मैं पश्चिम बंगाल के पूर्व और पश्चिम मिदनापुर जिले में कालियाथई-कपलेश्वरी बर्दी थाला की जलनिकासी योजना तथा मुर्शिदाबाद, में कांदी उप-मंडल की मास्टर प्लान हेतु बजटीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

71. पश्चिम बंगाल में वैकल्पिक पत्तन सुविधा के विकास की आवश्यकता को देखते हुए सागर हौप में एक परियोजना तैयार करने का प्रस्ताव है। उचित समय पर आवश्यक निधियों प्रदान की जाएंगी।

समावेशी विकास

72. सं.प्र.ग. सरकार के लिए समावेशी विकास विश्वास का एक कार्य है। विगत पाँच वर्षों में, हमारी सरकार ने व्यक्ति के सूचना के अधिकार और अपने कार्य के अधिकार के लिए विधिक गारंटीयों द्वारा समर्थित हकदारियों का सृजन किया है। इसके पश्चात् वर्ष 2009-10 में शिक्षा के अधिकार का अधिनियम बना। अगले कदम के रूप में, अब हम खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रारूप के साथ तैयार हैं जिसे जल्द ही आम जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इन वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए, सामाजिक क्षेत्र पर होने वाला व्यथ क्रमिक रूप से बढ़ाकर 1,37,674 करोड़ रुपए किया गया है। यह 2010-11 में कुल आयोजना परिव्यय का 37 प्रतिशत है। आयोजना आवंटनों का अन्य 25 प्रतिशत ग्रामीण अवसंरचना के विकास हेतु रखा गया है। इससे होने वाले विकास और उत्पन्न अवसरों से हमें आशा है कि समावेशी विकास की प्रक्रिया और मजबूत होगी।

शिक्षा

73. बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 6 से 14 वर्ष के आयु-समूह के सभी बच्चों को समता और भेदभाव-रहित सिद्धांतों पर आधारित अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा की विधिक हकदारी हेतु, एक ढांचे के निर्माण का उल्लेख है। हाल के वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा हेतु नामांकन और अवसंरचना में सुधार लाने में सर्व शिक्षा अधियान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लगभग 98 प्रतिशत बस्तियां अंब प्राथमिक स्कूलों के दायरे में आती हैं। स्कूली शिक्षा के लिए, मैं वर्ष 2009-10 के 26,800 करोड़ रुपए के आयोजना आवंटन को बढ़ाकर वर्ष 2010-11 में 31,036 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, राज्यों को वर्ष 2010-11 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित अनुदानों के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए 3,675 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

स्वास्थ्य

74. सभी जिलों की जिला स्वास्थ्य रूपरेखा तैयार करने हेतु एक वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2010-11 में किया जाएगा। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों विशेषकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अत्यधिक फायदा होना चाहिए। इस मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाओं की सुपुर्दगी में होने वाले अंतरालों को सफलतापूर्वक दूर किया है।

75. मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन को 19,534 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 में 22,300 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वित्तीय समावेशन

76. बैंकिंग सेवाओं के फायदे 'आम आदमी' को पहुँचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ और

परामर्श करके 2000 से अधिक की जनसंख्या वाली बस्तियों में मार्च 2012 तक समुचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। लक्षित लाभ-भोगियों को बीमा और अन्य सेवाएं प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। ये सेवाएं समुचित प्रौद्योगिकी की सहायता से कारोबार सम्पर्की और अन्य मॉडलों का प्रयोग कर के प्रदान की जाएंगी। इस व्यवस्था से 60,000 बस्तियों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि

77. वर्ष 2007-08 में, सरकार ने बैंकिंग सेवा-रहित क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक वित्तीय समावेशन निधि और एक वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना की थी। वित्तीय समावेशन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से, मैं इनमें से प्रत्येक निधि के लिए 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव करता हूँ। ये भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबांड द्वारा दी जाएंगी।

ग्रामीण विकास

78. महात्मा गांधी के शब्दों में, "जिस प्रकार यह ब्रह्माण्ड स्वयं में विद्यमान है उसी प्रकार भारत गांवों में बसता है।" सं.प्र.ग. सरकार के लिए, ग्रामीण अवसंरचना का विकास एक उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। वर्ष 2010-11 के लिए मैं ग्रामीण विकास हेतु 66,100 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ।

79. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के चार वर्ष बीत चुके हैं। इस अवधि में यह सभी जिलों में कार्यान्वयन की गयी है और इसके अंतर्गत 4.5 करोड़ से अधिक परिवारों को लाया गया है। नरेंगा के लिए आवंटन वर्ष 2010-11 में बढ़ा कर 40,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारत निर्माण ने ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2010-11 में इन कार्यक्रमों के लिए, मैं 48,000 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

80. इंदिरा आवास योजना कमजोर वर्गों के लिए एक लोकप्रिय ग्रामीण आवास योजना है। भवन-निर्माण की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मैं इस योजना के तहत प्रति इकोई लागत बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों के लिए 45,000 रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 48,500 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 2010-11 के लिए, इस योजना का आवंटन बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

81. देश के पिछड़े जिलों में अवसंरचना अंतराल दूर करने की कार्यान्वयन के भाग के रूप में, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि एक प्रभावी साधन साबित हुई है। वर्ष 2010-11 के लिए इस निधि में, मैं वर्ष 2009-10 के 5,800 करोड़ रुपए के आवंटन में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर, 7,300 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैंने बुद्धेलखण्ड क्षेत्र में सूखे में कमी लाने हेतु 1,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की है।

शहरी विकास और आवास

82. शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु तैयार की गई "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" को, सामुदायिक भागीदारी, दक्षता विकास और स्वरोजगार सहायता ढाँचों पर ध्यान देकर, सुदूर

किया गया है। वर्ष 2010-11 के लिए, मैं शहरी विकास हेतु पिछले वर्ष के 3,060 करोड़ रुपए के आवंटन में 75 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर, 5,400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए 850 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 2010-11 में 1,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

83. वर्ष 2009-10 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने 10 लाख रुपए तक के आवास ऋणों, जिसमें मकान की लागत 20 लाख रुपए से अधिक न हो, पर एक प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता देने की योजना की घोषणा की थी। मैं इस योजना को 31 मार्च, 2011 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। तदनुसार, वर्ष 2010-11 में इस योजना के लिए मैं 700 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

84. विगत वर्ष मलिन बस्तियों के निवासियों और शहरी गरीबों के लिए राजीव आवास योजना की घोषणा उन राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी जो मलिन बस्तियों के निवासियों को सम्पत्ति का अधिकार प्रदान करने के इच्छुक हैं। अब यह योजना चलाए जाने के लिए तैयार है। मैं वर्ष 2010-11 के लिए, विगत वर्ष के 150 करोड़ रुपए की तुलना में 1,270 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रकार, इसमें 700 प्रतिशत की वृद्धि होती है। राजीव आवास योजना के कार्यान्वयन में सरकार का प्रयास राज्यों को प्रोत्साहित करना होगा जिससे भारत को शीघ्रातिशीघ्र स्लम-मुक्त बनाया जा सके।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

85. देश के स.घ.उ. में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान 8 प्रतिशत, विनिर्मित उत्पाद का 45 प्रतिशत और हमारे निर्यात का 40 प्रतिशत होता है। इनसे 2.6 करोड़ उद्यमों के जरिए लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री ने ऐसे कई मुद्दों, जो इस क्षेत्र के विकास को प्रभावित करते हैं, को सुलझाने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया। इस कार्यबल ने सभी हितधारकों के साथ विस्तृत परिचर्चा की और कार्यसूची तैयार की। सूक्ष्म और लघु उद्यम संबंधी एक उच्च स्तरीय परिषद् सिफारिशों और कार्यसूची के कार्यान्वयन की मौनिटरिंग करेगी। वर्ष 2010-11 में इस क्षेत्र के लिए, मैं 1,794 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 2,400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

86. व्यापक खादी सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच 22 दिसम्बर, 2009 को 150 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण संबंधी करार पर हस्ताक्षर हुए। इस कार्यक्रम के तहत 300 चुनिंदा खादी संस्थाएं आएंगी।

सूक्ष्म वित्तीय व्यवस्था

87. स्व-सहायता समूहों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्म वित्तीय व्यवस्था के रूप में उभरा है। इसे वर्ष 2005-06 में 200 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ 'सूक्ष्म-वित्तपोषण विकास और इक्विटी निधि' के रूप में युन: नामित किया गया था। वर्ष 2010-11 में इस निधि की आधारभूत निधि को दुगुना कर 400 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

असंगठित क्षेत्र

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि

88. असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकताओं को देखते हुए, और असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 1,000 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक आवंटन के साथ एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यह निधि जुलाहों, ताड़ी बनाने वालों, रिक्षा चालकों, बीड़ी निर्माण में लगे कामगारों आदि हेतु बनायी गयी योजनाओं को सहायता प्रदान करेगी।

89. सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए 1 अक्टूबर, 2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से लागू हुई और इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए, ऐसे सभी महात्मा गांधी नरेंगा लाभार्थियों जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 15 से अधिक दिन तक कार्य किया है, को इसके फायदे प्रदान करने का प्रस्ताव है।

90. असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवानिवृत्त के लिए स्वेच्छापूर्वक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने और नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अभिदाताओं के लिए इस योजना की प्रचलन लागत कम करने के लिए, सरकार वर्ष 2010-11 में खोले गए प्रत्येक एनपीएस खाते में 1,000 रुपए प्रति वर्ष का अंशदान देगी। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एनपीएस में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए इस योजना "स्वावलम्बन" में 1,000 रुपए के न्यूनतम अंशदान और 12,000 रुपए प्रति वर्ष का अधिकतम अंशदान उपलब्ध होगा। यह योजना अन्य तीन वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। तदनुसार, वर्ष 2010-11 के लिए, मैं 100 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहा हूँ। इससे असंगठित क्षेत्र के 10 लाख एनपीएस अभिदाताओं को फायदा पहुंचेगा। इस योजना का प्रबंधन अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

91. मैं राज्य सरकारों से भी यह अपील करता हूँ कि वे इस योजना में समान राशि का अंशदान करें और समाज के दुर्बल वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में भागीदार बनें।

दक्षता विकास

92. प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद् ने दक्षता विकास संबंधी कार्यनीतियों के संचालन के लिए मुख्य विनियामक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इस परिषद् का मिशन वर्ष 2022 तक 50 करोड़ कुशल व्यक्ति तैयार करने का है। इनमें से राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम का लक्ष्य 15 करोड़ है, जिसने अक्टूबर, 2009 से अपना कार्य आरंभ किया है। इसने उच्च विकास वाले 21 क्षेत्रों का एक व्यापक दक्षता अंतराल अध्ययन पूरा किया है और एक लाख प्रति वर्ष की दर से 10 लाख कुशल जनशक्ति उत्पन्न करने के लिए 45 करोड़ रुपए की लागत वाली तीन परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। अन्य परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों पर विचार किया जा रहा है।

93. कपड़ा मंत्रालय की मौजूदा संस्थाओं और उपकरणों की क्षमता बढ़ाकर कपड़ा और परिधान क्षेत्र में व्यापक दक्षता विकास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र के संसाधनों का भी दोहन परिव्यय आधारित दृष्टिकोण के जरिए प्रशिक्षण को प्रोत्साहित कर किया जाएगा। इन उपकरणों के जरिए, कपड़ा मंत्रालय ने 5 वर्ष के दौरान 30 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

समाज कल्याण

94. मैं महिला और बाल विकास के लिए आयोजना परिव्यय में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव करता हूँ। 2009-10 में शुरू की गयी कई नयी पहल, अब कार्यान्वयन के लिए तैयार हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिशन तैयार किया जा रहा है। किशोरियों के लिए राजीव गांधी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आईसीडीएस के दायरे का विस्तार किया जा रहा है।

95. महिला साक्षरता दर में और सुधार लाने के लिए, सरकार ने पहले बनाए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को "साक्षर भारत" नामक नए कार्यक्रम के रूप में पुनः बनाया है। इसे 7 करोड़ निरक्षर वयस्कों के लक्ष्य के साथ सितम्बर, 2009 में आरंभ किया गया। इसमें 6 करोड़ महिलाएं हैं।

96. महिला कृषकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आरंभ की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपसंघटक के रूप में इस परियोजना के लिए, मैंने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

97. माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का आयोजना परिव्यय बढ़ाकर 4500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूँ। यह राशि, 2009-10 की तुलना में, 80 प्रतिशत अधिक होगी। अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांग व्यक्तियों, विच्छिन्न नागरिकों और एल्कोहल के और नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के पीड़ितों को शामिल करते हुए, यह लक्षित जनसंख्या वर्गों के लिए कार्यान्वयन किए जा रहे कार्यक्रमों की सहायता करेगी। इस बढ़ोत्तरी के साथ मंत्रालय, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीमों के तहत छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन कर सकेगा। यह बहुत समय से लम्बित रहा है।

98. इस आवंटन से बधारों के फायदे के निमित्त भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी। दो संयुक्त क्षेत्रीय निःशक्त व्यक्ति केन्द्रों के साथ-साथ, जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, 50 अतिरिक्त जिलों में की जा रही है।

99. मैं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए भी वर्ष 2010-11 के आयोजना आवंटन को, 1,740 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,600 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि है। माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए, मुझे खुशी हो रही है कि हम, मौजूदा वर्ष में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत उधार देने का लक्ष्य हासिल करने के निकट हैं। इसे आगामी तीन वर्षों के लिए कायम रखा जाएगा।

पारदर्शिता और सरकारी जबाबदेहिता का सुदृढ़ीकरण

100. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने देश में सरकारी संस्थाओं के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबाबदेहिता को सुसाध्य बनाने वाले माहील के सूचन हेतु गंभीर प्रयास किया है। जैसाकि माननीय सदस्यों को पता है, इस संबंध में अनेक विधायी और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं।

वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग

101. वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने वाले हमारे अधिकांश विधान बहुत पुराने हैं। विभिन्न समय पर इन अधिनियमों में बड़ी संख्या में किए गए संशोधनों ने भी अस्पष्टता और जटिलता बढ़ाई है। सरकार इस सेक्टर को अपेक्षाओं की तर्ज पर लाने के लिए वित्तीय सेक्टर के कानूनों को दोबारा लिखने तथा स्पष्ट करने के लिए वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव करती है।

प्रशासनिक सुधार आयोग

102. प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन, यूपीए सरकार द्वारा अपने पहले कार्यकाल में किया गया था। इसने 15 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, जिनमें से, 10 रिपोर्टों की जांच सरकार द्वारा की गई है। अब तक कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात 800 सिफारिशों में से, 350 सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जा चुका है तथा 450 कार्यान्वयन की जा रही हैं।

भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण

103. मैंने, अपने पिछले बजट भाषण में, भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण का गठन करने, इसके व्यापक कार्यकरण सिद्धांतों और पहली अनन्य पहचान संख्याओं के प्रदाय समर्थ-सीमा की घोषणा की थी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि यह प्राधिकरण गठित कर लिया गया है। यह आगामी वर्ष में अनन्य पहचान संख्याओं का पहला सैट जारी करने की अपनी वचनबद्धताएं पूरी करने में समर्थ होगा। यह वित्तीय समावेशन और लक्षित संबिंदी भुगतानों के लिए प्रभावी मंत्र प्रदान करेगा। चूंकि भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण अब प्रचलनात्मक चरण में प्रवेश कर जाएगा, मैं 2010-11 के लिए इस प्राधिकरण को 1,900 करोड़ रुपए आवंटित करता हूँ।

अनन्य परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह

104. प्रभावी कर प्रशासन और वित्तीय अभिशासन प्रणाली के लिए ऐसी आईटी परियोजनाओं के सूचन की आवश्यकता है, जो विश्वसनीय, सुरक्षित और सक्षम हों। आईटी परियोजनाएं जैसे कर सूचना नेटवर्क, नई पेंशन योजना, राष्ट्रीय राजकोष प्रबंधन एंजेंसी, व्यय सूचना नेटवर्क, वस्तु एवं सेवा कर विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। विभिन्न प्रौद्योगिकीय और प्रणाली विषयक मामलों की जांच करने के लिए, मैं श्री नंदन निलोकानी की अध्यक्षता में एक अनन्य परियोजना प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय

105. सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का निष्पक्ष और विषयपरक मूल्यांकन करने के लिए और सरकारी कार्यक्रमों की कारगरता बढ़ाने

हेतु एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। यह निर्णय लिया गया है कि यह उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में अभिशासी बोर्ड के अधीन एक स्वतंत्र निकाय होगा। यह स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय अग्रगामी फलैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा और अपने निष्कर्षों को लोक क्षेत्र में रखेगा। इसके लिए निधियां योजना आयोग द्वारा दी जाएंगी।

भारतीय रुपए के लिए प्रतीक

106. आगामी वर्ष में, हम भारतीय रुपए के लिए एक प्रतीक को औपचारिक रूप देना चाहते हैं जो भारतीय लोकाचारों और संस्कृति को प्रतिबिम्बित और समाहित करे। इसके साथ भारतीय रुपया भी अमरीकी डालर, ब्रिटिश पौण्ड स्टर्लिंग, यूरो और जापनी येन, जैसे चुनिंदा मुद्रा क्लब में सम्मिलित हो जाएगा। इन देशों की स्पष्ट विशिष्ट पहचान है।

सुरक्षा और न्याय

107. सुरक्षित सीमाएं तथा जान-माल की सुरक्षा विकास को प्रोत्साहित करती हैं। मैं रक्षा के लिए आवंटन बढ़ाकर 1,47,344 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें पूँजी व्यय के लिए 60,000 करोड़ रुपए शामिल होगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए व्यवस्था की जाएगी।

108. वर्ष 2009-10 में, देश में समग्र आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति मोटे तौर पर नियंत्रण में रही। देश के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए बहुत से नए उपाए किए गए। इनमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी को कार्यशील बनाना, चार एनएसजी केन्द्रों की स्थापना, आसूचना ब्यूरो और इसके बहु-विषयक एजेंसी केन्द्र का विस्तार शामिल हैं।

109. वर्ष 2009 में, जम्मू-कश्मीर में हिंसा में कमी आयी। हमने अनेक विश्वास निर्माण संबंधी उपाय किए हैं। एक और ऐसे उपाय के रूप में, सरकार वर्ष 2010 में, पांच केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में लगभग 2,000 युवाओं को कांस्टेबल नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है।

110. तीनीस लेफ्ट विंग अंतिवाद प्रभावित जिलों की विकास संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए, विकास और सुरक्षा उपायों के बीच समन्वित प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य बल गठित किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि योजना आयोग प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकीकृत कार्य योजना तैयार करेगा। इस कार्य योजना की सहायता करने के लिए पर्याप्त निधियां मुहैया करायी जाएंगी। मैं, गुमराह हुए लोगों से हिंसा छोड़ने और विकास प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह करता हूँ।

राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधिक सुधार मिशन

111. सभी को समय पर न्याय दिलाने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधिक सुधार मिशन की स्थापना करने की मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य न्यायालयों में वर्तमान में 15 वर्ष के औसत से लंबित विधिक मामले 2012 तक 3 वर्ष में कम करके सहायता करना है। यह व्यापार के लिए विधिक माहौल सुधारने में भी सहायता करेगा। तेरहवें वित्त आयोग ने न्याय प्रदाय सुधारने के लिए

राज्यों को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, जिसमें वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रम का सुदृढ़ीकरण भी शामिल है।

बजट अनुमान 2010-11

अब मैं 2010-11 के बजट अनुमानों की ओर आता हूँ।

112. सकल कर प्राप्तियों के 7,46,651 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के 1,48,118 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2010-11 में केन्द्र को निवल कर राजस्व और व्यवस्थाएं तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संबंध में अनुमानित की गई हैं।

113. 2010-11 के बजट अनुमानों में कुल 11,08,749 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। यह ब.अ. 2009-10 में कुल व्यय की तुलना में 8.6 प्रतिशत अधिक है। ब.अ. 2010-11 में आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय क्रमशः 3,73,092 करोड़ रुपए और 7,35,657 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यद्यपि आयोजन व्यय में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आयोजना-भिन्न व्यय में, पिछले वर्ष के ब.अ. की तुलना में केवल 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयोजना व्यय के इस स्तर के साथ, मुझे विश्वास है कि कुल आयोजना व्यय, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित व्यय के 100 प्रतिशत के बहुत निकट होगा।

114. माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि राजकोषीय नीति को राजकोषीय विवेक के लिए अपेक्षित संरचना द्वारा मार्गदर्शित होना है। बजट 2009-10 के साथ, प्रस्तुत किए गए माध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में, मैंने राजकोषीय घाटे की रूपरेखा निर्धारित की थी। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि अपनी व्यवहारदृष्टि के मद्देनजर, मैं 5.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के साथ 2010-11 का बजट प्रस्तुत करने में समर्थ रहा हूँ। आज, अन्य बजट दस्तावेजों के साथ सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे माध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में, शीघ्रातिशीघ्र राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापस आने के लिए गंभीरता के साथ इस मुद्दे का समाधान करेगी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 2008-09 में 7.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की तुलना में, 2009-10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार तेल और उर्वरक बांडों सहित तुलनीय राजकोषीय घाटा 6.9 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटे के ये दोनों आंकड़े संशोधित स.घ.उ. संख्याओं पर आधारित हैं, जिनका प्रकाशन केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया गया है और इसमें पहले उल्लिखित इसी तरह की मद्दों को शामिल किया गया है। यह, मौजूदा वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में लगभग एक प्रतिशत का सुधार दर्शाता है। मैंने तेल और उर्वरक कम्पनियों को बांड जारी करने से बचाने के लिए विवेकपूर्ण सचेत प्रयास किए हैं। मैं नकदी के रूप में सरकारी आर्थिक सहायता देने

115. वर्ष 2009-10 का बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने राजकोषीय घाटे के उच्च स्तर के बारे में अपनी चिन्ता जतायी थी। मैंने यह भी कहा था कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापस आने के लिए गंभीरता के साथ इस मुद्दे का समाधान करेगी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 2008-09 में 7.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की तुलना में, 2009-10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार तेल और उर्वरक बांडों सहित तुलनीय राजकोषीय घाटा 6.9 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटे के ये दोनों आंकड़े संशोधित स.घ.उ. संख्याओं पर आधारित हैं, जिनका प्रकाशन केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया गया है और इसमें पहले उल्लिखित इसी तरह की मद्दों को शामिल किया गया है। यह, मौजूदा वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में लगभग एक प्रतिशत का सुधार दर्शाता है। मैंने तेल और उर्वरक कम्पनियों को बांड जारी करने से बचाने के लिए विवेकपूर्ण सचेत प्रयास किए हैं। मैं नकदी के रूप में सरकारी आर्थिक सहायता देने

की परिपाटी को जारी रखना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आर्थिक सहायता संबंधी देयताओं को हमारे राजकोषीय लेखाकरण में शामिल किया जा सका है।

116. वर्ष 2010-11 में स.घ.उ. का 5.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटा 3,81,408 करोड़ रुपए परिकलित होता है। राजकोषीय घाटे के लिए विभिन्न अन्य वित्तपोषण मदों के मदेनजर, 2010-11 में सरकार का वास्तविक निवल बाजार उधार 3,45,010 करोड़ रुपए होगा। निजी क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की पर्याप्त संभावना होगी। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परमर्श से, उधार कार्यक्रम की आयोजना बनाएगी।

भाग-ख

अध्यक्ष महोदया,

अब, मैं अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

117. उनको तैयार करते समय, मैंने सुदृढ़ कर प्रशासन के सिद्धांतों से मार्गदर्शन लिया है जैसाकि कौटिल्य के निम्नलिखित शब्दों में अंतर्निहित है :

“इस प्रकार, एक बुद्धिमान महा समाहर्ता राजस्व संग्रहण का कर्य इस प्रकार करेगा कि उत्पादन और उपभोग अनिष्ट रूप से प्रभावित न हों……लोक सम्पन्नता, प्रचुर कृषि उत्पादकता और अन्य बातों के साथ वाणिज्यिक समृद्धि पर वित्तीय सम्पन्नता निर्भर करती है।”

118. मैंने पिछले वर्ष कहा था कि कर सुधार एक प्रक्रिया है न कि एक घटना। मैंने प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में जिस प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की थी वह परिचर्चा पत्र के साथ प्रत्यक्ष कर सहित का मासौदा जारी करना थी। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सुधार की पहल के रूप में वस्तु एवं सेवा कर शुरू किया जाना था। मैंने अपने भाषण के भाग 'क' में, दोनों सुधार पहलों में घटनाक्रमों को प्रस्तुत किया है।

119. हमने, प्रत्यक्ष करों के प्रशासन में सेवा प्रदाय के प्रमुख क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण के मार्ग पर चलना जारी रखा है। यह करदाता और कर प्रशासन के बीच वास्तविक अन्तरामुख कम करेगा और कार्यप्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अपेक्षित परिवर्तन करने में तेजी लाएगा। बैंगलूरू में केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र अब पूरी तरह कार्यशील है और यह प्रतिदिन लगभग 20,000 विवरणियों पर कार्रवाई कर रहा है। इस अभियान को वर्ष के दौरान और दो केन्द्रों की स्थापना करके आगे बढ़ाया जाएगा।

120. नागरिक केन्द्रित अभियान की ओर अग्रसर होने के लिए सरकार के कार्यक्रम के भाग के रूप में आय कर विभाग ने पुणे, कोची और चंडीगढ़ में आय कर सेवा केन्द्रों के माध्यम से “सेवोत्तम” की शुरुआत की है। यह सभी आवेदनों के पंजीकरण के लिए एकल विन्डो प्रणाली प्रदान करते हैं, जिसमें शिकायत निवारण तथा कागजी विवरणियां भी शामिल हैं। इस वर्ष यह योजना चार और शहरों में कार्यान्वयित की जाएगी।

121. अप्रैल, 2011 तक वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का उद्देश्य हासिल करने के लिए, केन्द्र और राज्यों में अप्रत्यक्ष कर प्रशासनों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित अपनी आंतरिक कार्य-

प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि परियोजना एसीईसी—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचलन इस वर्ष, देशभर में, पहले से ही प्रचलित हो गया है। इससे कर प्रशासन में अधिक पारदर्शित आएगी और करदाता सेवाओं की सुपुर्दी में सुधार होगा। इसी प्रकार, राज्यों में वाणिज्यिक करों के कम्प्यूटरीकरण के लिए हाल ही में एक मिशन मोड परियोजना अनुमोदित की गई है। 1133 करोड़ रुपये के पवित्र में केन्द्र का हिस्सा 800 करोड़ रुपये है, जिससे इस परियोजना से वस्तु एवं सेवा कर शुरू करने की आधारशिला रखी जाएगी।

122. मैंने पिछले वर्ष उल्लेख किया था कि आयकर विवरणी प्रपत्र सरल और प्रयोक्ता अनुकूल होने चाहिए। आयकर विभाग आगामी निर्धारण वर्ष के लिए व्यष्टि वेतनभोगी करदाताओं के लिए सरल-II प्रपत्र अधिसूचित करने के लिए अब तैयार है। इस प्रपत्र से व्यष्टि एक सरल प्रपत्र में केवल दो पृष्ठों में संगत ब्लैर भर पाएंगे।

123. करदाताओं के साथ विवादों के शीघ्र निपटान के लिए मैं उन मामलों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूँ जिन्हें समझौता आयोग द्वारा स्वीकार किया जा सकता है ताकि निर्धारण के लिए लम्बित तलाशी और जब्ती के मामलों से संबंधित कार्यवाहियां शामिल की जा सकें। मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क के संबंध में समझौता आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का भी प्रस्ताव करता हूँ ताकि उसके क्षेत्राधिकार की परिधि के बाहर के कतिपय प्रकार के मामले स्वीकार किए जा सकें।

124. पिछले वर्ष कानून में किए गए संसोधनों से सरकार सार्वभौम राष्ट्रों के अलावा विशिष्ट राज्य क्षेत्रों के साथ कर संधियां करने में समर्थ हुई। हमने बैंक से संबंधित और अन्य सूचना का आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता शुरू की है ताकि विदेश में रहने वाले अनिवासियों की करवांचना का कारगर तरीके से पता लगाया जा सके और अप्रकटित आस्तियों की पहचान की जा सके।

प्रत्यक्ष कर

मैं, अब प्रत्यक्ष करों पर आता हूँ।

125. मैंने पिछले वर्ष सभी करदाताओं की छूट सीमा बढ़ाकर और व्यक्तिगत आयकर पर अधिभार हटाकर व्यष्टि करदाताओं को राहत दी थी। करदाताओं ने उचित कर देकर इन रियायतों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दी हैं। वर्तमान कर-स्लैबों को व्यापक करके और राहत देने के लिए, मैं इन कर-स्लैबों का इस प्रकार प्रस्ताव करता हूँ :

1.6 लाख रुपये तक आय

शून्य

1.6 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये
तक आय

10 प्रतिशत

5 लाख रुपये से अधिक और 8 लाख रुपये
तक आय

20 प्रतिशत

8 लाख रुपये से अधिक आय

30 प्रतिशत

126. कर-स्लैबों के इस प्रस्तावित विस्तार से बहुत बड़ी संख्या में करदाताओं को काफी राहत मिलेगी।

127. बचत को बढ़ावा देने के साथ-साथ अवसरंचना के महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए उनका उपयोग सुनिश्चित करने हेतु, मैं केन्द्र सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित दीर्घावधिक अवसरंचना बांडों में निवेश करने के लिए 20,000 रुपये की अतिरिक्त राशि की कटौती करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। यह, कर बचतों पर । लाख रुपये की मौदूदा सीमा के अतिरिक्त होगी। मुझे विश्वास है कि इन राहतों से उपभोग के साथ-साथ बचत के लिए व्यष्टि करदाताओं के पास अधिक धन होगा।

128. स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जिनके लिए इस समय आयकर अधिनियम के अंतर्गत कटौती की अनुमति है, मैं अंशदान करने के अतिरिक्त, मैं इसी प्रावधान के तहत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अंशदान करने के लिए भी कटौती के रूप में अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

129. अधिभार को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की अपनी पहल आगे बढ़ाते हुए, मैं घरेलू कम्पनियों पर लगने वाले 10 प्रतिशत का मौजूदा अधिभार घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही, मैं न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की दर में बढ़ोतरी करके इसे बही लाभों की 15 प्रतिशत की वर्तमान दर से 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे कारपोरेट करदाताओं के बीच आपस में समानता का संवर्धन होगा।

130. राष्ट्रपति ने जून 2009 में संसद को संबोधित अपने अधिभाषण में इस दशक को 'नवोन्मेष दशक' के रूप में घोषित किया था। पिछले वर्ष, मैंने एक छोटी नकारात्मक सूची छोड़कर, सभी विनिर्माण व्यवसायों के लिए आंतरिक अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर उपगत व्यय पर दी जाने वाली भारित कटौती का कार्यक्षेत्र बढ़ाया था। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, मैं अब आंतरिक अनुसंधान और विकास पर उपगत व्यय पर भारित कटौती बढ़ाकर 150 प्रतिशत से 200 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संघों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को किए गए भुगतानों पर भारित कटौती बढ़ाकर 125 प्रतिशत से 175 प्रतिशत किए जाने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

131. इस समय, किसी अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ को किया गया कोई भी भुगतान भारित कटौती के लिए पात्र है। अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ की आय आयकर से मुक्त है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि समाज विज्ञानों में अनुसंधान अधिकार सार्थकीय अनुसंधान में लगे अनुमोदित संघों को किए गए भुगतानों को 125 प्रतिशत की भारित कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसे अनुमोदित अनुसंधान संघों की आय कर मुक्त होगी।

132. मैंने पिछले वर्ष के अपने बजट भाषण में कहा था कि लाभ आधारित कटौतियां अपने आप में सक्षम नहीं हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए, मैंने लाभ आधारित कटौती के विकल्प के रूप में निवेश आधारित कटौती की शुरुआत की है। पर्यटन क्षेत्र, जिसमें अधिक

रोजगार की संभावना है, मैं निवेश को बढ़ावा देने के लिए, मैं भारत में दो स्टार अथवा उससे अधिक के श्रेणी वाले नए होटलों को इस अधिनियम के तहत निवेश आधारित कटौती का फायदा देने का प्रस्ताव करता हूँ।

133. वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित आवास और स्थावर संपदा क्षेत्र को एक बारगी अंतरिम राहत देने के लिए, मैं उनके लाभों पर कटौती का दावा करने के लिए लम्बित परियोजनाएं चार वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष की अवधि में पूरी करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं आवासीय परियोजनाओं में दुकानों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के निर्मित क्षेत्र के मापदंडों में ढील देने का भी प्रस्ताव करता हूँ ताकि उनके निवासियों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।

134. 40 लाख रुपये से अधिक का कारोबार वाले सभी व्यवसायों से इस समय अपने खातों की लेखा-परीक्षा करवा लिया जाना अपेक्षित होता है। इसी तरह का प्रावधान उन सभी व्यवसायों पर भी लागू होता है जिनकी प्राप्तियां 10 लाख रुपये से अधिक होती हैं। मैंने वित्त मंत्री के रूप में 1984 के अपने बजट में ये सीमाएं निर्धारित की थीं। यह छोटे करदाताओं पर पड़ने वाला अनुपालन भार कम करने का समय है। इसलिए, मैं ये सीमाएं व्यापार के मामले में 60 लाख रुपये और व्यवसाय के मामले में 15 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

135. छोटे करदाताओं के कारोबार प्रचालन को सुसाध्य बनाने के लिए, मैंने 40 लाख रुपये तक कारोबार वाले सभी छोटे व्यवसायों के लिए अनुमानित कराधान का कार्यक्षेत्र विस्तृत किया था। छोटे करदाताओं पर पड़ने वाले अनुपालन भार को और कम करने के लिए, मैं अब यह सीमा 60 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

136. भुगतानों की प्रारंभिक सीमाएं जिनके नीचे सोत पर कर कटौती नहीं की जाती है, लम्बे समय से अपरिवर्तित बनी हुई हैं। मैं ये प्रारंभिक सीमाएं युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ।

137. व्यय की अनुमति न देने के मौजूदा प्रावधान शिथिल करते हुए, मैं ऐसे व्यय की कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ, यदि वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय कर की कटौती की गई है और वह विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से पहले अदा कर दिया गया है। इससे, अधिकांश कटौती करवाने वाले को अगले वित्त वर्ष के सितम्बर तक अतिरिक्त समय मिलेगा। इसके साथ-साथ, मैं काटे गए लेकिन विनिर्दिष्ट तिथि तक जमा न किए गए कर पर भारित ब्याज बढ़ाकर इसे 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

138. पिछले वर्ष, मैंने सामान्य भागीदार फर्मों के लिए लागू विद्यमान मापदंडों के अनुसार, नई शुरू की गई सीमित देनदारी भागीदारी (एलएलपी) के कराधान के लिए व्यवस्था की थी। छोटी कम्पनियों को एलएलपी में रूपान्तरण आसान बनाने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह, पूँजीगत लाभ कर के अध्यधीन नहीं होगा।

139. इस अधिनियम के मौजूदा उपबंधों के तहत, “आम जन सुविधा की किसी अन्य वस्तु की प्रत्युति”, “धर्मार्थ प्रयोजन” के रूप में नहीं मानी जा सकती, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार स्वरूप में कोई कार्यकलाप किया जाता है। मुझे कई संगठनों से अन्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इस प्रतिबंध में कुछ ढील देने की मांग की गई थी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, यदि ऐसे कार्यकलापों से हुई आय एक वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

140. प्रत्यक्ष कर संबंधी मेरे प्रस्तावों से इस वर्ष 26,000 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने का अनुमान है।

अप्रत्यक्ष कर

141. अप्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्ताव तैयार करने में जिन्होंने मेरा पथ प्रदर्शन किया, वे प्रमुख उद्देश्य आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बाधा पहुँचाएं बिना, और जीएसटी के पथ पर अग्रसर होते हुए कुछ सीमा तक राजकोषीय समेकन हासिल करने के लिए जरूरी हैं।

142. मेरे प्रस्तुत किए गए पिछले बजट के समय के विपरीत, अर्थव्यवस्था के सुधार के संकेत अब अधिक व्यापक और स्पष्ट हैं। सरकार द्वारा दिए गए लगातार तीन राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों से सुधार की प्रक्रिया को काफी मदद मिली है। हमारे आर्थिक निष्पादन में हुई बेहतरी तब भी राजकोषीय सुधार को प्रोत्साहित करती है, जब वैशिक स्थिति सावधानी बरतने की मांग करती है। इसलिए, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों में कटौती दर आंशिक रूप से वापस लेने तथा सभी गैर-पेट्रोलियम उत्पादों पर मानक दर बढ़ाकर यथामूल्य 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। पोर्टलैंड सीमेंट तथा किलंकर सीमेंट पर प्रयोज्य शुल्क की विशिष्ट दरें भी आनुपातिक रूप से समायोजित की जा रही हैं और अधिक रखी जा रही हैं। इसी तरह, बड़ी कारों, बहु उपयोगी वाहनों तथा खेल में प्रयुक्त वाहनों पर उत्पाद शुल्क का यथामूल्य घटक, जो प्रथम प्रोत्साहन पैकेज के भाग के रूप में घटाया गया था, में 2 प्रतिशतांक की बढ़ोतरी करके 22 प्रतिशत किया जा रहा है।

143. पेट्रोलियम की कीमतों में होने वाली अनियमित घट-बढ़ के चलते, सरकार ने जून, 2008 में कच्चे पेट्रोलियम को बुनियादी सीमा शुल्कों से पूरी छूट दी और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों पर बुनियादी शुल्क में आनुपातिक कटौती की थी। उस समय की 112 अमेरीकी डालर प्रति बैरल के भारतीय कच्चे तेल समूह की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की तुलना में कीमतें इस समय बहुत कम हैं। राजकोषीय समेकन के पथ पर फिर से अग्रसर होने की जबर्दस्त जरूरत को देखते हुए, मैं कच्चे पेट्रोलियम पर 5 प्रतिशत; डीजल और पेट्रोल पर 7.5 प्रतिशत तथा अन्य परिष्कृत उत्पादों पर 10 प्रतिशत के बुनियादी शुल्क को बहाल करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में प्रति लीटर 1-1 रुपये की बढ़ोतरी करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

144. चूंकि मैंने कई वर्ष पहले धूम्रपान करना छोड़ दिया था, इसलिए मैं अन्य लोगों को भी इसे छोड़ने की सलाह देना चाहूँगा।

765 GZ/10-4

क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस संबंध में, मैं दरों में कुछ बढ़ोतरी के साथ सिगरेट, सिगार और सिगारिलों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन कर रहा हूँ। मैं सुर्गांधित तम्बाकू, नसवार, चबाने वाला तम्बाकू, आदि, जैसे सभी गैर-धूम्रपान तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव भी करता हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं चबाने वाले तम्बाकू और ब्रांडेड अनियमित तम्बाकू के लिए पाऊच पैकिंग मशीनों की क्षमता पर आधारित एक यौगिक लेवी योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ।

145. मैं अब निरन्तर बृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ बहुत जरूरी प्रोत्साहनों पर आता हूँ।

कृषि और संबंधित क्षेत्र

146. मेरे भाषण में कृषि के विकास के लिए पहले रेखांकित की गई कार्यनीति के समर्थन में, मैं उन कुछ प्रमुख क्षेत्रों का समाधान करने का प्रस्ताव करता हूँ। जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाना जरूरी है। ये हैं :

- (i) नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के लिए एक मजबूत आपूर्ति शृंखला बनाना ताकि वे उपभोग और प्रसंस्करण केन्द्रों में शीघ्र पहुँचाए जा सकें;
- (ii) ऐसे उत्पादों को मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए अवसरंचना और प्रौद्योगिकी; और
- (iii) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल।

147. मधुमक्खी पालन, बागबानी, डेयरी, मुर्गीपालन, मांस, समुद्री मत्स्यपालन और जलीय जीव पालन जैसे संबंधित क्षेत्रों पर इसी तरह ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

148. इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव करता हूँ :

- खाद्यान्नों और चीनी के लिए “मॉडियो” अथवा भांडागारण में यंत्रीकृत प्रबंध प्रणाली और पैलेट रैकिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए 5 प्रतिशत के रियायती आयात का दर्जा देना और इसके साथ-साथ, ऐसे उपस्करों की स्थापना और उन्हें चालू करने हेतु सेवा कर से पूरी तरह छूट देना।
- निम्नलिखित की आरम्भिक स्थापना और विस्तार के लिए सेवा कर से पूरी छूट के साथ 5 प्रतिशत की रियायती सीमा शुल्क पर परियोजना आयात का दर्जा देना;
 - शीत भंडागरण, शीत कक्ष जिसमें परिरक्षण अथवा कृषि और संबंधित क्षेत्र के उत्पाद के भंडागरण हेतु खेत स्तर पर पूर्व-कूलर शामिल हैं, और
 - ऐसे उत्पाद के लिए प्रसंस्करण यूनिटें।
- प्रशीतित बैनों अथवा ट्रकों के विनियोग हेतु आवश्यक प्रशीतन यूनिटों को सीमा शुल्क से पूरी छूट।

149. मैं निम्नलिखित की व्यवस्था प्रदान करने का प्रस्ताव भी करता हूँ।

- भारत में निर्मित न होने वाली निर्दिष्ट कृषि मशीनरी पर 5 प्रतिशत का रियायती सीमा-शुल्क;
- कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के परिक्षण, भंडारण और प्रसंस्करण हेतु निर्दिष्ट उपस्करणों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट और उनके उत्पादों के भंडारण और भंडागरण पर सेवा कर से छूट; और
- कृषि में प्रयोग होने वाले ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट।

150. वर्ष 2003 में बागान क्षेत्र में प्रयोग के लिए निर्दिष्ट मशीनरी पर रियायती आयात शुल्क लगाया गया था। यह छूट जुलाई 2010 में समाप्त हो जाएगी। इस श्रम-प्रधान क्षेत्र का आधुनिकीकरण अभी प्रत्याशित स्तर पर पहुँचना है। इसलिए मैं सीबीडी छूट सहित इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2011 तक करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है कि इससे इस क्षेत्र को वार्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में पर्याप्त समय मिल जाएगा।

151. कृषि उत्पादकता के लिए पूर्वाधारणाओं में से एक पूर्वाधारणा अच्छी गुणवत्ता वाले और रोग-रोधी बीजों तक पहुँच है। मैं कृषि बीजों के परीक्षण और प्रमाणन को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

152. मैं, सड़क मार्ग से की जाने वाली अनाजों और दालों की दुलाई को सेवा कर से छूट का भी प्रस्ताव करता हूँ। रेलवे द्वारा की जाने वाली इनकी दुलाई को छूट मिलती रहेगी।

153. मैं, आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित लघु उद्योग क्षेत्र के विनिर्माताओं के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति सहज बनाने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत दो उपायों का प्रस्ताव करता हूँ। पहला, उन्हें पूंजीगत सामान पर उनकी प्राप्ति के वर्ष में एक किस्त में अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का पूरा ऋण लेने की अनुमति होगी। दूसरा, उन्हें मासिक के बजाए, त्रैमासिक आधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चुकाने की अनुमति होगी। इन उपायों के 1 अप्रैल 2010 से लागू हो जाने पर उन्हें काफी राहत मिलनी चाहिए।

पर्यावरण

154. जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को काम में लेने को, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अब एक विश्वसनीय कार्ययोजना के रूप में मान्यता मिली है। घोषित राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष की निधियों के निर्माण हेतु, मैं भारत में उत्पादित कोयले पर 50 रुपये प्रति टन की सामान्य दर पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह उपकर आयातित कोयले पर भी लागू होगा।

155. राष्ट्रीय सौर मिशन क्रियान्वित करने के सरकार के संकल्प के अनुपालन में; मैं फोटोवोल्टिक और सौर ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों की आरम्भिक स्थापना हेतु अपेक्षित मशीनरी, उपस्कर,

उपकरण और यंत्रों आदि पर 5 प्रतिशत का रियायती सीमा-शुल्क प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं उन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इसी तरह, भू-तापीय ऊर्जा का दोहन करने में प्रयोग होने वाले भूतल स्रोत ताप पम्प बुनियादी सीमा-शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क से मुक्त होंगे।

156. पवन ऊर्जा ने हाल के वर्षों में देश में आशाजनक वृद्धि दर्शायी है। अतिरिक्त राहत के उपाय के रूप में; मैं पवन ऊर्जा जेनरेटरों के लिए रोटर ब्लॉडों के विनिर्माण हेतु अपेक्षित कुछ और निर्दिष्ट निविष्टियों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूँ।

157. लेड लाइट्स गलियों, घरों और कार्यालयों के लिए रोशनी के अंत्यंत ऊर्जा किफायती स्रोत के रूप में श्रीगणेश कर रही है। इन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंपों के समतुल्य 4 प्रतिशत किया जा रहा है।

158. बिजली की कारों और वाहनों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट दी गई थी। ये पेट्रोल अथवा डीजल वाहनों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकल्प पेश करते हैं। ऐसे वाहनों के विनिर्माताओं ने उनकी निविष्टियों और हिस्सों पर अदा किए गए शुल्क को निष्प्रभावित करने में कठिनाई व्यक्त की है। मैं ऐसे वाहनों पर 4 प्रतिशत का सामान्य उत्पाद शुल्क लगाकर इसका समाधान करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं ऐसे वाहनों के कुछ महत्वपूर्ण पुर्जों अथवा लघु पुर्जे जोड़ने को वास्तविक प्रयोक्ता स्थिति के अध्यधीन बुनियादी सीमा-शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूँ। इन पुर्जों को 4 प्रतिशत का रियायती सीबीडी भी मिलता रहेगा।

159. साधारण साइकिल रिक्षा का अब परिवहन के पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में स्वागत किया जा रहा है। सीएसआईआर ने मानव चालित रिक्षाओं के स्थान पर “सोलेक्शा” नामक एक नया उत्पाद विकसित किया है। यह बैटरियों से चलता है जो सौर ऊर्जा से चार्ज होता है। मैं इस उत्पाद को 4 प्रतिशत कारियायती उत्पाद-शुल्क प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके महत्वपूर्ण पुर्जों और हिस्सों को भी सीमा-शुल्क से छूट दी जा रही है।

160. बायो-डिग्रेडेबल सामग्रियों का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए, मैं कम्पोस्ट योग्य पालीमर के आयात को बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूँ।

आधारभूत संरचना

161. सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करना जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने का एक अन्य साधन है। मैं “शहरी परिवहन हेतु मोनोरेल परियोजनाओं” को 5 प्रतिशत के रियायती उत्पाद-शुल्क पर परियोजना आयात दर्जा देने का प्रस्ताव करता हूँ।

162. सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट मशीनरी को इस शर्त पर आयात-शुल्क से पूर्ण छूट उपलब्ध है कि यह मशीनरी न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि में बेची या निपटायी नहीं जाएगी। ऐसे अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए कि इससे मशीनरी बेकार हो जाती है, मैं हासित मूल्य पर आयात-शुल्क अदा करने पर ऐसी मशीन को

पुनः बेचने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि आयातक ऐसी मशीनरी को अन्य पात्र सड़क निर्माण परियोजनाओं में लगाने के लिए स्वतंत्र है।

163. 14 मिलियन प्रतिमाह के हिसाब से अधिदाता आधार बढ़ने के चलते, भारत विश्व में मोबाइल फोन कनेक्शनों के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में एक है। मोबाइल फोनों का घरेलू उत्पादन, उनके पुरजों, हिस्सों और अनुरूपियों के लिए बुनियादी, सीवीडी और विशेष अतिरिक्त शुल्कों से प्रदान की गयी छूटों को देखते हुए, अब जोर पकड़ रहा है। अनुरूपियों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, ये छूटें अब बैटरी चार्जरों और हैंड-फोनों के पुरजों को भी दी जा रही हैं। विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट की वैधता को भी 31 मार्च, 2011 तक बढ़ाया जा रहा है।

चिकित्सा क्षेत्र

164. चिकित्सा उपस्कर, उपकरण और यंत्र बहुत जटिल आयात शुल्क प्रणाली के अध्यधीन आते हैं। ये अनेक लंबी सूचियों पर आधारित होते हैं और इनमें अलग-अलग मर्दों का विवरण दिया होता है। विवरणों के साथ बहुल दरें टैरिफ लाईनों के अनुरूप न होने के कारण विवाद होते हैं और कई बार अत्यधिक उपस्कर छूट का लाभ लेने से विचित्र रह जाते हैं। मैं सभी चिकित्सा उपस्करों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट सहित एक समान 5 प्रतिशत रियायती बुनियादी शुल्क और 4 प्रतिशत का सीवीडी प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसे उपस्करों, जबकि वे सीवीडी और विशेष अतिरिक्त शुल्क से मुक्त होंगे, के विनिर्माण हेतु हिस्सों और यंत्रों पर 5 प्रतिशत का रियायती बुनियादी शुल्क निर्धारित किया जा रहा है जबकि वे सीवीडी और विशेष अतिरिक्त शुल्क से मुक्त होंगे। चिकित्सा उपस्करों और सहायक मशीनों, पुनर्वास सहायता यंत्रों आदि जैसी मशीनों को इस समय उपलब्ध पूर्ण छूट जारी रखी जा रही है। सरकारी अस्पतालों अथवा किसी कानून के अधीन स्थापित अस्पतालों को उपलब्ध रियायत भी कायम रखी जा रही है।

165. अस्थि विकलांग संबंधी यंत्र विनिर्माताओं ने अध्यावेदन दिया है कि उनके यंत्रों पर तैयार उत्पाद की तुलना में शुल्क की उच्च दर लगती है। मैं ऐसे यंत्रों के विनिर्माण हेतु निर्दिष्ट निविष्टियों को आयात शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूं।

सूचना एवं मनोरंजन

166. भारत एक सिनेमा ऐरोपी राष्ट्र है। द्विरावृति हेतु फिल्मों के डिजीटल मास्टर के आयात करने अथवा चलचित्रकला फिल्म पर आयातित की तुलना में इलैक्ट्रानिक माध्यम पर भारित वितरण में विभेदक सीमा-शुल्क संरचना के कारण फिल्म उद्योग मुश्किलों का सामना करता रहा है। मैं वाहक माध्यम के मूल्य पर ही सीमा-शुल्क प्रभारित करते हुए इसे युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। यही विधान द्विरावृति के लिए आयातित संगीत और गेमिंग साप्टवेयर पर लागू होगा। भारतीय सिनेमा की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, मैं इसका विस्मयकारी पटाक्षेप कर रहा हूं। ऐसे सभी मामलों में बौद्धिक अधिकारों का अंतरण प्रस्तुत करने वाला मूल्य सेवा कर के अध्यधीन होगा।

167. डिजीटल प्राद्योगिकी अपनाए जाने से सूचना एवं मनोरंजन का केवल परिवर्तन के दौर में है। बहु-विषयी सेवा प्रदाताओं को "डिजीटल हैंड एंड" उपस्कर में निवेश करने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए, मैं ऐसी परियोजनाओं की आरंभिक स्थापना हेतु विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट के साथ 5 प्रतिशत के रियायती सीमा-शुल्क पर परियोजना आयात दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

कीमती धातुएं

168. कीमती धातुओं की कीमतें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। चूंकि इन पर विशेष अतिरिक्त शुल्क दरों पर सीमा-शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है, मैं इन दरों को निम्नानुसार सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव करता हूं :

- सोने और प्लेटिनम पर 200 रुपये प्रति 10 ग्राम से 300 रुपये प्रति 10 ग्राम;
- चांदी पर 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम से 1,500 रुपये प्रति किलोग्राम।

169. रत्न और जवाहरात हमारे निर्यात समूह में एक परंपरागत मद है। रेडियम-जवाहरात पर पालिश करने में प्रयुक्त होने वाली एक कीमती धातु पर 10 प्रतिशत का बुनियादी सीमा-शुल्क लगता है। इसे घटाकर 2 प्रतिशत किया जा रहा है।

170. सोने की घरेलू परिशोधन क्षमता बढ़ाने के लिए, मैं स्वर्ण अयस्क और सांद्रों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट के साथ बुनियादी सीमा-शुल्क यथा मूल्य 2 प्रतिशत से घटाकर स्वर्ण तत्व के प्रति 10 ग्राम 140 रुपये का विशेष शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त, ऐसे अयस्क अथवा सांद्र से बनाए गए परिशोधित स्वर्ण पर उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 280 रुपये प्रति 10 ग्राम का विशेष शुल्क लगाया जा रहा है।

अन्य प्रस्ताव

171. उन खेलों के सामान, जो निर्यात की मद के रूप में महत्व प्राप्त कर रहे हैं, के विनिर्माण हेतु अपेक्षित निर्दिष्ट निविष्टियों अथवा कच्ची सामग्रियों को आयात शुल्क से पूर्ण छूट उपलब्ध है। कुछ और मर्दों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है।

172. माइक्रोवेव ओवेन्स के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं इसके महत्वपूर्ण हिस्सों में एम नामसः मैग्नेट्रोन्स पर बुनियादी सीमा-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

173. वर्तमान में, व्यक्तिगत सामान के रूप में वाणिज्यिक सेम्पल्स के शुल्क-मुक्त आयात पर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की मूल्य सीमा है। मैं, इस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं।

174. उद्योग जगत ने निवेदन किया है कि वापसियों पर आधारित 4 प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त शुल्क छूट के कारण निधियों का अत्यधिक अवरोध होता है। इस कठिनाई को आसान बनाने के लिए, मैं खुदरा बिक्री हेतु पहले से ही पैक आकार में आयातित वस्तुओं को विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्णतया छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता

हूं। इसमें मोबाइल फोन, घड़ियां और सिलेसिलाए बस्त्र चाहे वे पहले से ऐक आकार में आयात न किए गए हों, भी शामिल होंगे। नए विधान द्वारा शामिल न किए गए मामलों के लिए भी वापसी-आधारित छूट बनाए रखी जा रही है।

175. खिलौना गुब्बारे लाखों बच्चों की खुशी का स्रोत है। उनकी माताओं के चेहरे पर मुस्कान के लिए, मैं उन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

176. मैं निम्नानुसार कुछ अन्य राहत उपायों का प्रस्ताव करता हूं :

- पीपलामूल पर बुनियादी सीमा-शुल्क 70 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करना;
- हींग पर बुनियादी सीमा-शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना;
- आरओ प्रौद्योगिकी पर आधारित वाटर फिल्टरों को छोड़कर,
- घरेलू प्रकार के वाटर फिल्टरों हेतु प्रतिस्थापनीय किटों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करके 4 प्रतिशत करना;
- नालीदार डिब्बों और कार्टनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना;
- लेटेक्स रबड़ धागे पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना; और
- औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम के अधीन शामिल की गई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना।

177. सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मेरे कर प्रस्तावों के परिणामस्वरूप, इस वर्ष 43,500 करोड़ रुपए का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है।

सेवा कर

178. सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान करता है। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद में सेवा कर अनुपात लगभग 1 प्रतिशत ही है। इस तरह, इस क्षेत्र में राजस्व बढ़ने की काफी संभावना है।

179. इस अंतर को पाठने के लिए, मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए तीसरे प्रोत्साहन पैकेज से पहले वाली सेवा कर की दर बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का मेरे पास विकल्प था। मैं विकास की गति बनाए रखने और वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों की दरों में समाभिरूपता लाने के लिए भी इस विकल्प का सहारा नहीं ले रहा हूं। इसलिए, मैं वस्तु और सेवा कर का मार्ग प्रशास्त करने के लिए सेवाओं पर कर की दर 10 प्रतिशत बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूं।

180. मेरे पास सभी सेवाओं को सेवा कर के अंतर्गत लाने का दूसरा विकल्प था। मैं इनमें से किसी का चयन इस चरण में नहीं कर रहा हूं। फिर भी मैं अब तक कर से छूटी कुछ सेवाओं को सेवा कर उगाही के क्षेत्राधिकार में लाने का प्रस्ताव करता हूं। ये अलग से अधिसूचित की जा रही हैं।

181. मैं राजस्व हानियों को रोकने, गड़बड़ियां समाप्त करने और पिछले कुछ समय से उत्पन्न कठिपय शंकाओं को दूर करने के लिए कुछ विधायी परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव करता हूं। मैं इन ब्यौरों का विस्तृत वर्णन करने के लिए सदन का कीमती समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये वित्त विधेयक और अन्य बजट दस्तावेजों में उपलब्ध हैं।

182. सेवाओं का निर्यात विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसर्विसिंग के क्षेत्र में प्रचुर रोजगार सृजित करता है और विदेशी मुद्रा लाता है। मैं, सेवाओं के निर्यात की परिभाषा और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन करते हुए, सेवाओं के निर्यातकों को संचित ऋण की वापसी की प्रक्रिया सरल बनाने का प्रस्ताव करता हूं।

183. प्रत्यायित समाचार एजेंसियां, जो ऑनलाइन समाचार देती हैं, पर सेवा कर लगता है। समाचार का प्रसार-प्रचार करने में ऐसी समाचार एजेंसियों की स्वैच्छिक सेवाओं को देखते हुए, मैं कतिपय मानदंड पूरा करने वाली ऐसी समाचार एजेंसियों को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

184. सेवा कर से संबंधित मेरे प्रस्ताव से इस वर्ष 3,000 करोड़ रुपये का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है।

185. सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में परिवर्तन लाने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

186. प्रत्यक्ष करों संबंधी मेरे प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, इस वर्ष 26,000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष करों संबंधी प्रस्ताव के परिणामस्वरूप वर्ष 46,500 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होने का अनुमान है। मेरे कर प्रस्ताव में दी जा रही रियायतों और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किए गए उपायों के मददेनजर इस वर्ष 20,500 करोड़ रुपए का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है।

187. हम वैश्विक मंदी से किसी अन्य राष्ट्र की तुलना में अधिक शीघ्रता से बाहर निकले हैं। मैंने विगत वर्ष के कार्य के तरीके पर अपना निर्णय देने में संकोच नहीं किया और अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। आज, हमारे कार्य हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे।

188. यह बजट 'आम आदमी' का है। यह किसानों, कृषकों, उद्यमियों और निवेशकों का है। बढ़िया अवसर है। यह सही समय है। मैंने ऐसे लोगों के हाथों पर भरोसा किया है, जिन्हें मैं जानता हूं, उन पर राष्ट्रीय हित में किसी भी अवसर पर खड़े होने के लिए विश्वास किया जा सकता है। मैंने राष्ट्र के सामूहिक विवेक पर भरोसा किया है जिनका आगामी वर्षों में अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए सहारा लिया जा सकता है।

189. अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूं।"

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2010

No. F. 2(12)B(D)/2010.—The following is published for general information :—

"Budget 2010-2011

Speech of

Pranab Mukherjee

Minister of Finance

February 26, 2010

Madam Speaker,

I rise to present the Union Budget for 2010-11.

In 2009, when I presented the interim Budget in February and the regular Budget in July in this august House, the Indian economy was facing grave uncertainties. Growth had started decelerating and the business sentiment was weak. The economy's capacity to sustain high growth was under serious threat from the widespread economic slowdown in the developed world.

2. It was not clear to us, as also to the policy makers in many other countries, how this crisis would eventually unfold. What would be its impact on the growth momentum of the Indian economy? How soon will we be able to turnaround the fortunes of our economy? The short-term global outlook was bleak and the consensus was that year 2009 would face the brunt of this crisis across the world.

3. At home, there was added uncertainty on account of the delayed and sub-normal south-west monsoon, which had undermined the kharif crop in the country. There were concerns about production and prices of food items and its possible repercussions on the growth of rural demand.

4. Today, as I stand before you, I can say with confidence that we have weathered these crises well. Indian economy now is in a far better position than it was a year ago. That is not to say that the challenges today are any less than what they were nine months ago when UPA under the leadership of Mrs. Sonia Gandhi was elected back to power and Prime Minister Dr. Manmohan Singh formed the Government for the second term.

5. The three challenges and the medium term perspective that I had outlined in my last Budget Speech remain relevant, even today. These would continue to engage the Indian policy-planners for the next few years.

6. The first challenge before us is to quickly revert to the high GDP growth path of 9 per cent and then find the means to cross the 'double digit growth barrier'. This calls for imparting a fresh momentum to the impressive recovery in growth witnessed in the past few months. In this endeavour, I seek Lord Indra's help to make the recovery more broad-based in the coming months.

7. Growth is only as important as what it enables us to do and be. Therefore, the *second* challenge is to harness economic growth to consolidate the recent gains in making development more inclusive. The thrust imparted to the development of infrastructure in rural areas has to be pursued to achieve the desired objectives within a fixed time frame.

8. We have to strengthen food security, improve education opportunities and provide health facilities at the level of households, both in rural and urban areas. These are issues that require significant resources, and we have to find those resources.

9. The *third* challenge relates to the weaknesses in government systems, structures and institutions at different levels of governance. Indeed, in the coming years, if there is one factor that can hold us back in realising our potential as a modern nation, it is the bottleneck of our public delivery mechanisms. There have been many initiatives in this regard, in different sectors, at different points of time. Some of them have been effective in reforming the way the Government works in those areas. But we have a long way to go before we can rest on this count.

10. The Union Budget cannot be a mere statement of Government accounts. It has to reflect the Government's vision and signal the policies to come in future.

11. With development and economic reforms, the focus of economic activity has shifted towards the non-governmental actors, bringing into sharper focus the role of Government as an enabler.

12. An enabling Government does not try to deliver directly to the citizens everything that they need. Instead it creates an enabling ethos so that individual enterprise and creativity can flourish. Government concentrates on supporting and delivering services to the disadvantaged sections of the society.

13. It is this broad conceptualisation of the Budget that informs my speech today. I would now begin by presenting a brief overview of the economy.

Overview of the Economy

14. Yesterday, I laid on the table of the House the Economic Survey, which gives a detailed analysis of the economic situation of the country over the past twelve months. I intend to highlight only a few salient features that form the backdrop of this Budget.

15. The fiscal year 2009-10 was a challenging year for the Indian economy. The significant deceleration in the second half of 2008-09, brought the real GDP growth down to 6.7 per cent, from an average of over 9 per cent in the preceding three years. We were among the first few countries in the world to implement a broad-based counter-cyclical policy package to respond to the negative fallout of the global slowdown. It included a substantial fiscal expansion along with liberal monetary policy support.

16. The effectiveness of these policy measures became evident with fast paced recovery. The economy stabilised in the first quarter of 2009-10 itself, when it clocked a GDP growth of 6.1 per cent, as against 5.8 per cent in the fourth quarter of the preceding year. It registered a strong rebound in the second quarter, when the growth rate rose to 7.9 per cent. With the Advance Estimates placing the likely growth for 2009-10 at 7.2 per cent, we are indeed vindicated in our policy stand. The final figure may well turn out to be higher when the third and fourth quarter GDP estimates for 2009-10 become available.

17. This recovery is very encouraging for it has come about despite a negative growth in the agriculture sector. More importantly, it is the result of a renewed momentum in the manufacturing sector and marks the rise of this sector as the growth driver of the economy. The growth rate in manufacturing in December 2009 was 18.5 per cent—the highest in the past two decades. There are also signs of a turnaround in the merchandise exports with a positive growth in November and December 2009 after a decline of about twelve successive months. Export figures for January are also encouraging. Significant private investment can now be expected to provide the engine for sustaining a growth of 9 per cent per annum. With some luck, I hope to breach the 10 per cent mark in not-too-distant a future.

18. A major concern during the second half of 2009-10 has been the emergence of double digit food inflation. There was a momentum in food prices since the flare-up of global commodity prices preceding the financial crisis in 2008, but it was expected that the agriculture season beginning June 2009 would help in moderating the food inflation. However, the erratic monsoons and drought like conditions in large parts of the country reinforced the supply side bottlenecks in some of the essential commodities. This set in motion inflationary expectations. Since December 2009, there have been indications of these high food prices, together with the gradual hardening of the fuel product prices, getting transmitted to other non-food items as well. The inflation data for January seems to have confirmed this trend.

19. Government is acutely conscious of this situation and has set in motion steps, in consultation with the State Chief Ministers, which should bring down the inflation in the next few months and ensure that there is better management of food security in the country.

CONSOLIDATING GROWTH

20. Managing a complex economy is a difficult task, more so when it is a growing economy in a globalised world. And yet, choices have to be made and they have to be well-timed.

21. After successfully managing the effects of the global slowdown, we need to strengthen the domestic macroeconomic environment to help consolidate the rebound in growth and sustain it over the medium term. We need to review the stimulus imparted to the economy and move towards the preferred path of fiscal consolidation

that facilitated the remarkable growth in the pre-crisis five year period. We need to make growth more broad-based and ensure that supply-demand imbalances are better managed.

Fiscal Consolidation

22. The success of the fiscal stimulus in supporting domestic demand could be traced to its composition. The approach of the Government was to increase the disposable income in the hands of the people by effecting reductions in indirect taxes and by expanding public expenditure on programmes like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and rural infrastructure. Now that the recovery has taken root, there is a need to review public spending, mobilise resources and gear them towards building the productivity of the economy.

23. In shaping the fiscal policy for 2010-11, I have acted on the recommendations of the Thirteenth Finance Commission. It has recommended a calibrated exit strategy from the expansionary fiscal stance of last two years. The Commission has recommended a capping of the combined debt of the Centre and the States at 68 per cent of the GDP to be achieved by 2014-15.

24. As a part of the fiscal consolidation process, it would be for the first time that the Government would target an explicit reduction in its domestic public debt-GDP ratio. I intend to bring out, within six months, a status paper giving a detailed analysis of the situation and a road map for curtailing the overall public debt. This would be followed by an annual report on the subject.

Tax reforms

25. I am happy to inform the Honourable Members that the process for building a simple tax system with minimum exemptions and low rates designed to promote voluntary compliance, is now nearing completion. On the Direct Tax Code the wide-ranging discussions with stakeholders have been concluded. I am confident that the Government will be in a position to implement the Direct Tax Code from April 1, 2011.

26. On Goods and Services Tax, we have been focusing on generating a wide consensus on its design. In November, 2009, the Empowered Committee of the State Finance Ministers placed the first discussion paper on GST in the public domain. The Thirteenth Finance Commission has also made a number of significant recommendations relating to GST, which will contribute to the ongoing discussions. We are actively engaged with the Empowered Committee to finalise the structure of GST as well as the modalities of its expeditious implementation. It will be my earnest endeavour to introduce GST along with the DTC in April, 2011.

People's ownership of PSUs

27. While presenting the Budget for 2009-10, I invited people to participate in Government's disinvestment programme to share in the wealth and prosperity of the Central Public Sector Undertakings.

28. Since then, ownership has been broad based in Oil India Limited, NHPC, NTPC and Rural Electrification Corporation while the process is on for National Mineral Development Corporation and Sathuj Jal Vidyut Nigam. The Government will raise about Rs. 25,000 crore during the current year. Through this process, I propose to raise a higher amount during the year 2010-11. The proceeds will be utilised to meet the capital expenditure requirements of social sector schemes for creating new assets.

29. Listing of Central Public Sector Undertakings improves corporate governance besides unlocking the value for all stakeholders—the Government, the company and the shareholders. Market capitalization of five companies which have been listed since October, 2004 has increased by 3.8 times from the book value of Rs. 78,841 crore to Rs. 2,98,929 crore.

30. The effective management of public expenditure by bringing it in line with the Government's objectives is a part of the fiscal consolidation process. This calls for proper targeting of subsidies and expenditure adjustment.

Fertiliser subsidy

31. I had announced the intent of the Government for the fertiliser sector in my Budget Speech of 2009. A Nutrient Based Subsidy policy for the fertiliser sector has since been approved by the Government and will become effective from April 1, 2010. This policy is expected to promote balanced fertilization through new fortified products and focus on extension services by the fertiliser industry. This will lead to an increase in agricultural productivity and consequently better returns for the farmers. Over time, the policy is expected to reduce volatility in the demand for fertiliser subsidy in addition to containing the subsidy bill. Government will ensure that nutrient based fertiliser prices for transition year 2010-11, will remain around MRPs currently prevailing. The new system will move towards direct transfer of subsidies to the farmers.

Petroleum and Diesel pricing policy

32. In the last Budget, the constitution of an Expert Group, to advise the Government on a viable and sustainable system of pricing of petroleum products, was announced. The Group headed by Shri Kirit Parikh has submitted its recommendations to the Government. Decision on these recommendations will be taken by my colleague, the Minister of Petroleum & Natural Gas, in due course.

33. I am very happy to inform the Honourable Members that we have not only adhered to the fiscal roadmap that I had presented as a part of the Budget documents last year, but we have improved upon it. Except for meeting the liabilities of the year 2008-09, we have not issued oil or fertiliser bonds. I shall come to the numbers when I refer to the budget estimates a little later.

Improving Investment Environment

Foreign Direct Investment

34. Foreign Direct Investment (FDI) inflows during the year have been steady in spite of the decline in global

capital flows. India received FDI equity inflows of US\$ 20.9 billion during April-December, 2009 compared to US\$ 21.1 billion during the same period last year.

35. Government has taken a number of steps to simplify the FDI regime to make it easily comprehensible to foreign investors. For the first time, both ownership and control have been recognised as central to the FDI policy, and methodology for calculation of indirect foreign investment in Indian companies has been clearly defined. A consistent policy on downstream investment has also been formulated. Another major initiative has been the complete liberalization of pricing and payment of technology transfer fee, trademark, brand name and royalty payments. These payments can now be made under the automatic route.

36. Government also intends to make the FDI policy user-friendly by consolidating all prior regulations and guidelines into one comprehensive document. This would enhance clarity and predictability of our FDI policy to foreign investors.

Financial Stability and Development Council

37. The financial crisis of 2008-09 has fundamentally changed the structure of banking and financial markets the world over. With a view to strengthen and institutionalise the mechanism for maintaining financial stability, Government has decided to setup an apex-level Financial Stability and Development Council. Without prejudice to the autonomy of regulators, this Council would monitor macro prudential supervision of the economy; including the functioning of large financial conglomerates, and address inter-regulatory coordination issues. It will also focus on financial literacy and financial inclusion.

Banking Licences

38. The Indian banking system has emerged unscathed from the crisis. We need to ensure that the banking system grows in size and sophistication to meet the needs of a modern economy. Besides, there is a need to extend the geographic coverage of banks and improve access to banking services. In this context, I am happy to inform the Honourable Members that the RBI is considering giving some additional banking licenses to private sector players. Non Banking Financial Companies could also be considered, if they meet the RBI's eligibility criteria.

Public Sector Bank Capitalisation

39. During 2008-09, the Government infused Rs. 1900 crore as Tier-I capital in four public sector banks to maintain a comfortable level of Capital to Risk Weighted Asset Ratio. An additional sum of Rs. 1200 crore is being infused now. For the year 2010-11, I propose to provide a sum of Rs. 16,500 crore to ensure that the Public Sector Banks are able to attain a minimum 8 per cent Tier- I capital by March 31, 2011.

Recapitalisation of Regional Rural Banks

40. Regional Rural Banks (RRBs) play an important role in providing credit to rural economy. The capital of these banks is shared by the Central Government sponsor banks

and State Governments. The banks were last capitalised in 2006-07. I propose to provide further capital to strengthen the RRBs so that they have adequate capital base to support increased lending to the rural economy.

Corporate Governance

41. Improvement in corporate governance and regulation is an important part of the overall investment environment in the country. Government has introduced the Companies Bill, 2009 in the Parliament, which will replace the existing Companies Act, 1956. The proposed new bill will address issues related to regulation in corporate sector in the context of the changing business environment.

Exports

42. Government has provided interest subvention of 2 per cent on pre-shipment export credit up to March 31, 2010 for exports in certain sectors. I propose to extend the interest subvention of 2 per cent for one more year for exports covering handicrafts, carpets, handlooms and small and medium enterprises.

Special Economic Zones (SEZs)

43. The SEZs have attracted significant flows of domestic and foreign investments. In first three quarters of 2009-10 exports from SEZs recorded a growth of 127 per cent over the corresponding period last year. Government is committed to ensuring continued growth of SEZs to draw investments and boost exports and employment.

Agriculture Growth

44. The agriculture sector occupies centre-stage in our resolve to promote inclusive growth, enhance rural incomes and sustain food security. To spur the growth in this sector, the Government intends to follow a four-pronged strategy covering (a) agricultural production; (b) reduction in wastage of produce; (c) credit support to farmers; and (d) a thrust to the food processing sector.

45. The first element of the strategy is to extend the green revolution to the eastern region of the country comprising Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Eastern UP, West Bengal and Orissa, with the active involvement of Gram Sabhas and the farming families. For the year 2010-11, I propose to provide Rs. 400 crore for this initiative.

46. In the 60th year of the Republic, it is proposed to organise 60,000 "pulses and oil seed villages" in rain-fed areas during 2010-11 and provide an integrated intervention for water harvesting, watershed management and soil health, to enhance the productivity of the dry land farming areas. I propose to provide Rs. 300 crore for this purpose. This initiative will be an integral part of the Rashtriya Krishi Vikas Yojana.

47. The gains already made in the green revolution areas have to be sustained through conservation farming, which involves concurrent attention to soil health, water conservation and preservation of biodiversity. I propose an allocation of Rs. 200 crore for launching this climate resilient agriculture initiative.

48. The second element of the strategy relates to reduction of significant wastages in storage as well as in the operations of the existing food supply chains in the country. This needs to be addressed. As the Prime Minister has said recently, "We need greater competition and therefore need to take a firm view on opening up of the retail trade." It will help in bringing down the considerable difference between the farm gate prices, wholesale prices and retail prices.

49. There is wastage of grain procured for buffer stocks and public distribution system due to acute shortage of storage capacity in the Food Corporation of India. This deficit in the storage capacity is met through an ongoing scheme for private sector participation where the FCI has been hiring godowns from private parties for a guaranteed period of 5 years. This period is now being extended to 7 years.

50. The third element of the strategy relates to improving the availability of credit to farmers. I am happy to inform the Honourable Members that banks have been consistently meeting the targets set for agriculture credit flow in the past few years. For the year 2010-11, the target has been raised to Rs. 3,75,000 crore from Rs. 3,25,000 crore in the current year.

51. The Debt Waiver and Debt Relief Scheme for Farmers was a major initiative of the UPA Government. In view of the recent drought in some States and the severe floods in some other parts of the country, I propose to extend by six months the period for repayment of the loan amount by farmers from December 31, 2009 to June 30, 2010.

52. In the last budget, I had provided an additional one per cent interest subvention as an incentive to those farmers who repay their short-term crop loans as per schedule. I propose to raise this subvention for timely repayment of crop loans from one per cent to two per cent for 2010-11. Thus, the effective rate of interest for such farmers will now be five per cent per annum. Necessary provision in the Budget has been made.

53. The fourth element of the strategy aims at lending a further impetus to the development of food processing sector by providing state-of-the art infrastructure. In addition to the ten mega food park projects already being set up, the Government has decided to set up five more such parks.

54. As a part of the farm to market initiative, External Commercial Borrowings will henceforth be available for cold storage or cold room facility, including for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agricultural and allied produce, marine products and meat. Changes in the definition of infrastructure under the ECB policy are being made.

Infrastructure

55. Accelerated development of high quality physical infrastructure, such as roads, ports, airports and railways

is essential to sustain economic growth. While addressing the policy gaps in this sector, I propose to maintain the thrust for upgrading infrastructure in both rural and urban areas. In the Budget for 2010-11, I have provided Rs. 1,73,552 crore, which accounts for over 46 per cent of the total plan allocations, for infrastructure development in the country.

56. To make a visible impact in the road sector, Government has targeted construction of national highways (NHs) at the pace of 20 km per day. To push the pace of implementation, changes have been made in the policy framework, especially in respect of projects being executed through public private partnerships (PPPs). For the year 2010-11, I propose to raise the allocation of road transport by over 13 per cent from Rs. 17,520 crore to Rs. 19,894 crore.

57. Honourable Members have already heard from the Railway Minister about the large investments required to modernise and expand the network. I have provided Rs. 16,752 crore in the Budget for 2010-11 for Railways to lend her a helping hand. This is about Rs. 950 crore more than last year, when a substantial increase was made in the budgetary support for Railways.

58. To complement the dedicated freight corridor, the Delhi-Mumbai Industrial Corridor project has been taken up for integrated regional development. Preparatory activities have been completed for creation of six industrial investment nodes with eco-friendly world class infrastructure.

India Infrastructure Finance Company Limited

59. Government established the India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) to provide long-term financial assistance to infrastructure projects. Its disbursements are expected to touch Rs. 9,000 crore by end March 2010 and reach around Rs. 20,000 crore by March 2011. IIFCL has also been authorised to refinance bank lending to infrastructure projects. It has refinanced Rs. 3,000 crore during the current year and is expected to more than double that amount in 2010-11. The take-out financing scheme announced in the last Budget is expected to initially provide finance for about Rs. 25,000 crore in the next three years.

Energy

60. Government accords the highest priority to capacity addition in the power sector. The framework for induction of super critical technology in large capacity power plants of National Thermal Power Corporation is now in place. The Mega Power Policy has been modified and is now consistent with the National Electricity Policy, 2005 and Tariff Policy, 2006. It will help in lowering the cost of generation and the cost of power purchased by distribution utilities. I have more than doubled the plan allocation for power sector from Rs. 2,230 crore in 2009-10 to Rs. 5,130 crore in 2010-11. This does not include allocations for RGGVY, which is a part of Bharat Nirman.

61. Coal is the mainstay of India's energy sector and 75 per cent of the power generation is currently coal based. It is proposed to introduce a competitive bidding process for allocating coal blocks for captive mining to ensure greater transparency and increased participation in production from these blocks.

62. Government proposes to take steps to set up a "Coal Regulatory Authority" to create a level playing field in the coal sector. This would facilitate resolution of issues like economic pricing of coal and benchmarking of standards of performance.

63. The Jawaharlal Nehru National Solar Mission envisages establishing India as a global leader in solar energy. An ambitious target of 20,000 MW of solar power by the year 2022 has been set under the mission. I propose to increase the plan outlay for the Ministry of New and Renewable Energy by 61 per cent from Rs. 620 crore in 2009-10 to Rs. 1,000 crore in 2010-11.

64. The Ladakh region of Jammu and Kashmir faces an extremely harsh climate and suffers from energy deficiency. To address this problem, it is proposed to set up solar, small hydro and micro power projects at a cost of about Rs. 500 crore.

Environment and Climate change

65. To ameliorate the negative environmental consequences and increased pollution levels associated with industrialisation and urbanisation, I propose to take a number of proactive steps in the Budget 2010-11.

National Clean Energy Fund (NCEF)

66. There are many areas of the country where pollution levels have reached alarming proportions. While we must ensure that the principle of "polluter pays" remains the basic guiding criteria for pollution management, we must also give a positive thrust to development of clean energy. I propose to establish a National Clean Energy Fund for funding research and innovative projects in clean energy technologies. I shall outline the mode of funding for this initiative in Part B of my speech.

Effluent Treatment Plant, Tirupur

67. The textile cluster for knitwear in Tirupur in Tamil Nadu is a major contributor to the country's hosiery exports. I propose to provide a one-time grant of Rs. 200 crore to the Government of Tamil Nadu towards the cost of installation of a zero liquid discharge system at Tirupur to sustain this industry, which provides livelihood to lakhs of persons, without undermining the environment.

Special Golden Jubilee Package for Goa

68. I propose to provide a sum of Rs. 200 crore as a Special Golden Jubilee package for Goa to preserve the natural resources of the State by restoring Goa's beaches which are prone to erosion, and increasing its green cover through sustainable forestry.

National Ganga River Basin Authority (NGRBA)

69. The "Mission Clean Ganga 2020" under the National Ganga River Basin Authority (NGRBA) with the objective

that no untreated municipal sewage or industrial effluent will be discharged into the national river has already been initiated. I propose to double the allocation for NGRBA in 2010-11 to Rs. 500 crore.

70. I am happy to inform the Honourable Members that schemes on bank protection works along river Bhagirathi and river Ganga-Padma in parts of Murshidabad and Nadia district of West Bengal have been included in the Centrally Sponsored Flood Management Programme. I also propose to provide budgetary support for drainage scheme of Kaliaghari-Kapaleswari Baghri basin in the district of Purba and Paschim Midnapore, and Master Plan of Kandi sub-division in Murshidabad, West Bengal.

71. Recognising the need for developing an alternate port facility in West Bengal, it is proposed to develop a project at Sagar Island. Necessary funds will be provided in due course.

INCLUSIVE DEVELOPMENT

72. For the UPA Government, inclusive development is an act of faith. In the last five years, our Government has created entitlements backed by legal guarantees for an individual's right to information and her right to work. This has been followed-up with the enactment of the right to education in 2009-10. As the next step, we are now ready with the draft Food Security Bill which will be placed in the public domain very soon. To fulfil these commitments the spending on social sector has been gradually increased to Rs. 1,37,674 crore which now stands at 37 per cent of the total plan outlay in 2010-11. Another 25 per cent of the plan allocations are devoted to the development of rural infrastructure. With growth and the opportunities that it generates, we hope to further strengthen the process of inclusive development.

Education

73. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 creates a framework for legal entitlements for all children in the age group of 6 to 14 years to education of good quality, based on principles of equity and non-discrimination. In recent years, Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) has made significant contribution in improving enrolment and infrastructure for elementary education. About 98 per cent of habitations are now covered by primary schools. I propose to increase the plan allocation for school education from Rs. 26,800 crore in 2009-10 to Rs. 31,036 crore in 2010-11. In addition, States will have access to Rs. 3,675 crore for elementary education under the Thirteenth Finance Commission grants for 2010-11.

Health

74. An Annual Health Survey to prepare the District Health Profile of all Districts shall be conducted in 2010-11. The findings of the Survey should be of immense benefit to major public health initiatives particularly the National Rural Health Mission, which has successfully addressed the gaps in the delivery of critical health services in rural areas.

75. I propose to increase the plan allocation for the Ministry of Health and Family Welfare, from Rs. 19,534 crore to Rs. 22,300 crore for 2010-11.

Financial Inclusion

76. To reach the benefits of banking services to the '*Aam Aadmi*', the Reserve Bank of India had set up a High Level Committee on the Lead Bank Scheme. After careful assessment of the recommendations of this Committee, and in further consultation with the RBI, it has been decided to provide appropriate Banking facilities to habitations having population in excess of 2000 by March, 2012. It is also proposed to extend insurance and other services to the targeted beneficiaries. These services will be provided using the Business Correspondent and other models with appropriate technology back up. By this arrangement, it is proposed to cover 60,000 habitations.

Financial Inclusion Fund (FIF) and the Financial Inclusion Technology Fund

77. In 2007-08 the Government had set up a Financial Inclusion Fund and a Financial Inclusion Technology Fund in NABARD, to reach banking services to the unbanked areas. To give momentum to the pace of financial inclusion, I propose an augmentation of Rs. 100 crore for each of these funds, which shall be contributed by Government of India, RBI and NABARD.

Rural Development

78. In the words of Mahatma Gandhi "*Just as the universe is contained in the self, so is India contained in the villages*". For UPA Government, development of rural infrastructure remains a high priority area. For the year 2010-11, I propose to provide Rs. 66,100 crore for Rural Development.

79. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme has completed four years of implementation during which it has been extended to all districts covering more than 4.5 crore households. The allocation for NREGA has been stepped up to Rs. 40,100 crore in 2010-11. Bharat Nirman has made a substantial contribution to the upgradation of rural infrastructure through its various programmes. For the year 2010-11, I propose to allocate an amount of Rs. 48,000 crore for these programmes.

80. Indira Awas Yojana is a popular rural housing scheme for weaker sections. Taking note of the increase in the cost of construction, I propose to raise the unit cost under this scheme to Rs. 45,000 in the plain areas and to Rs. 48,500 in the hilly areas. For the year 2010-11, the allocation for this scheme is being increased to Rs. 10,000 crore.

81. As a part of the strategy to bridge the infrastructure gap in backward districts of the country, the Backward Region Grant Fund has proved to be an effective instrument. I propose to enhance the allocation to this fund by 26 per cent from Rs. 5,800 crore in 2009-10 to Rs. 7,300 crore in 2010-11. I have also provided an additional central

assistance of Rs.1,200 crore for drought mitigation in the Bundelkhand region in the Budget.

Urban Development and Housing

82. "Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana" designed to provide employment opportunities in urban areas, has been strengthened with focus on community participation, skill development and self-employment support structures. For the year 2010-11, I propose to increase the allocation for urban development by more than 75 per cent from Rs. 3,060 crore to Rs. 5,400 crore. In addition, the allocation for Housing and Urban Poverty Alleviation is also being raised from Rs. 850 crore to Rs. 1,000 crore in 2010-11.

83. While presenting the Union Budget for the year 2009-10, I had announced a Scheme of one per cent interest subvention on housing loans up to Rs. 10 lakhs where the cost of the house does not exceed Rs. 20 lakhs. I propose to extend this Scheme up to March 31, 2011. Accordingly, I propose to provide a sum of Rs. 700 crore for this Scheme for the year 2010-11.

84. The Rajiv Awas Yojana (RAY) for slum dwellers and urban poor was announced last year to extend support to States that are willing to provide property rights to slum dwellers. This scheme is now ready to take off. I propose to allocate Rs. 1,270 crore for 2010-11 as compared to Rs. 150 crore last year. This marks an increase of over 700 per cent. The Government's efforts in the implementation of RAY would be to encourage the States to create a slum free India at the earliest.

Micro, Small and Medium Enterprises

85. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) contribute 8 per cent of the country's GDP, 45 per cent of the manufactured output and 40 per cent of our exports. They provide employment to about 6 crore persons through 2.6 crore enterprises. To resolve a number of issues which affect the growth of this sector, Prime Minister constituted a High-Level Task Force which held detailed discussions with all stakeholders and drew up an agenda for action. A High Level Council on Micro and Small Enterprises will monitor the implementation of the recommendations and the agenda for action. I propose to raise the allocation for this sector from Rs. 1,794 crore to Rs. 2,400 crore for the year 2010-11.

86. A loan agreement for US \$ 150 million has been signed between the Government of India and the Asian Development Bank on 22nd December, 2009 for implementing the comprehensive Khadi Reforms Programme. This programme will cover 300 selected Khadi institutions.

Micro Finance

87. The programme for linking Self Help Groups (SHGs) with the banking system has emerged as the major micro-finance initiative in the country. It was re-designated as the 'Micro-Finance, Development and Equity Fund' in 2005-06 with a corpus of Rs. 200 crore. The fund corpus is being doubled to Rs. 400 crore in 2010-11.

Unorganised Sector

National Social Security Fund for unorganised sector workers

88. Recognising the need for providing social security to the workers in the unorganised sector, and as a follow up to the unorganised Sector Workers Social Security Act, 2008, it has been decided to set up a National Social Security Fund for unorganised sector workers with an initial allocation of Rs. 1,000 crore. This fund will support schemes for weavers, toddy tappers, rickshaw pullers, bidi workers etc.

89. The Government had launched *Rashtriya Swasthya Bima Yojana* on October 1, 2007 to provide health insurance cover to below poverty line workers and their families. It became operational on April 1, 2008 and so far more than 1 crore smart cards have been issued under this scheme. In view of the success of the scheme, it is now proposed to extend its benefits to all such Mahatma Gandhi NREGA beneficiaries who have worked for more than 15 days during the preceding financial year.

90. To encourage the people from the unorganised sector to voluntarily save for their retirement and to lower the cost of operations of the New Pension Scheme (NPS) for such subscribers, Government will contribute Rs. 1,000 per year to each NPS account opened in the year 2010-11. This initiative, "*Swavalamban*" will be available for persons who join NPS, with a minimum contribution of Rs. 1,000 and a maximum contribution of Rs. 12,000 per annum during the financial year 2010-11. The scheme will be available for another three years. Accordingly, I am making an allocation of Rs. 100 crore for the year 2010-11. It will benefit about 10 lakh NPS subscribers of the unorganised sector. The scheme will be managed by the interim Pension Fund Regulatory and Development Authority.

91. I also appeal to the State Governments to contribute a similar amount to the scheme and participate in providing social security to the vulnerable sections of the society.

Skill Development

92. Prime Minister's Council on National Skill Development has laid down the core governing principles for operating strategies for skill development. The Council has a mission of creating 50 crore skilled people by 2022. Of these, the target for the National Skill Development Corporation, which has started functioning from October, 2009, is 15 crore. It has completed a comprehensive skill gap study of 21 high growth sectors and approved three projects worth about Rs. 45 crore to create 10 lakh skilled manpower at the rate of one lakh per annum. Other projects are in advanced stages of consideration.

93. It is proposed to launch an extensive skill development programme in the textile and garment sector by leveraging the strength of existing institutions and instruments of the Textile Ministry. The resources of the private sector will also be harnessed by incentivising training through an outcome-based approach. Through

these instruments, the Ministry of Textiles has set an ambitious target of training 30 lakh persons over 5 years.

Social Welfare

94. I propose to step up the plan outlay for Women and Child Development by almost 50 per cent. Several new initiatives that were launched in 2009-10 are now ready for implementation. A mission for empowerment of women is being set up. The ICDS platform is being expanded for effective implementation of the Rajiv Gandhi Scheme for Adolescent Girls.

95. To further improve female literacy rate, the Government has recast the earlier National Literacy Mission as a new programme "*Saakshar Bharat*". It was launched in September, 2009 with a target of 7 crore non-literate adults which includes 6 crore women.

96. A Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana to meet the specific needs of women farmers is being launched. I have provided Rs. 100 crore for this initiative as a sub-component of the National Rural Livelihood Mission.

97. I am happy to inform the Honourable Members that I propose to enhance the plan outlay of the Ministry of Social Justice and Empowerment to Rs. 4500 crore. This amounts to an increase of 80 per cent as compared to 2009-10. This will support the programmes being implemented for the target population groups covering the Scheduled Castes, Other Backward Classes, persons with disabilities, senior citizens and victims of alcoholism and substance abuse. With this enhancement, the Ministry will be able to revise rates of scholarship under its post-matric scholarship schemes for SCs and OBC students, which is long overdue.

98. The allocation will also assist in establishing an Indian Sign Language Research and Training Centre for the benefit of the hearing impaired. District Disability Rehabilitation Centres are being set up in 50 additional districts along with two composite regional centres for persons with disabilities.

99. I also propose to raise the plan allocation for the Ministry of Minority Affairs from Rs. 1,740 crore to Rs. 2,600 crore for the year 2010-11. This marks an increase of nearly 50 per cent. I am happy to inform the Honourable Members that we are close to achieving the target of 15 per cent priority sector lending to minorities in the current year. This will be maintained for the next three years.

STRENGTHENING TRANSPARENCY & PUBLIC ACCOUNTABILITY

100. The UPA Government has made a serious attempt to create an environment that supports transparency and accountability in the working of the public institutions in the country. As Honourable Members are aware, a number of legislative and administrative measures have been taken in this regard.

Financial Sector Legislative Reforms Commission

101. Most of our legislations governing the financial

sector are very old. Large number of amendments to these Acts made at different points of time has also increased ambiguity and complexity. The Government proposes to set up a Financial Sector Legislative Reforms Commission to rewrite and clean up the financial sector laws to bring them in line with the requirements of the sector.

Administrative Reforms Commission

102. The Administrative Reforms Commission constituted by the UPA Government in its first term has submitted 15 reports, of which 10 reports have been examined by the Government. Out of the 800 identified recommendations for implementation so far, 350 recommendations have been implemented and 450 are under implementation.

Unique Identification Authority of India (UIDAI)

103. In my last Budget Speech, I had announced the constitution of the Unique Identification Authority of India, its broad working principles and the timelines for delivery of the first UID numbers. I am happy to report that the Authority has been constituted and it will be able to meet its commitments of issuing the first set of UID numbers in the coming year. It would provide an effective platform for financial inclusion and targeted subsidy payments. Since the UIDAI will now get into the operational phase, I am allocating Rs.1,900 crore to the Authority for 2010-11.

Technology Advisory Group for Unique Projects (TAGUP)

104. An effective tax administration and financial governance system calls for creation of IT projects which are reliable, secure and efficient. IT projects like Tax Information Network, New Pension Scheme, National Treasury Management Agency, Expenditure Information Network, Goods and Service Tax, are in different stages of roll out. To look into various technological and systemic issues, I propose to set up a Technology Advisory Group for Unique Projects under the Chairmanship of Shri Nandan Nilekani.

Independent Evaluation Office (IEO)

105. The Government had announced the setting-up of an Independent Evaluation Office to undertake impartial and objective assessments of the various public programmes and improve the effectiveness of the public interventions. It has been decided that it would be an independent entity under a Governing board chaired by the Deputy Chairman, Planning Commission. The IEO would evaluate the impact of flagship programmes and place the findings in the public domain. It would be funded by the Planning Commission.

Symbol for Indian Rupee

106. In the ensuing year, we intend to formalise a symbol for the Indian Rupee, which reflects and captures the Indian ethos and culture. With this, Indian Rupee will join the select club of currencies such as the US Dollar, British Pound Sterling, Euro and Japanese Yen that have a clear distinguishing identity.

Security and Justice

107. Secure borders and security of life and property

fosters development. I propose to increase the allocation for Defence to Rs.1,47,344 crore. This would include Rs.60,000 crore for capital expenditure. Needless to say, any additional requirement for the security of the nation will be provided for.

108. In 2009-10, the overall internal security and law and order situation in the country remained largely under control. Several new measures were taken by the Government to strengthen the security apparatus of the country. These include operationalisation of the National Investigation Agency (NIA), establishment of four NSG Hubs, augmentation of the Intelligence Bureau and its Multi-Agency Centre.

109. There was decline in violence in Jammu and Kashmir in the year 2009. We have taken a number of confidence building measures. As one more such measure, Government proposes to recruit about 2,000 youth as constables in five Central Para Military Forces in the year 2010.

110. To address the development problems of the thirty-three left wing extremism affected districts, a Task Force headed by the Cabinet Secretary was formed for promoting coordinated efforts across a range of development and security measures. It has been decided that Planning Commission will prepare an integrated action plan for the affected areas. Adequate funds will be made available to support the action plan. I appeal to the misguided elements to eschew violence and join the development process.

National Mission for Delivery of Justice and Legal Reforms

111. To provide timely delivery of justice to all, the Government has approved the setting up of the National Mission for Delivery of Justice and Legal Reforms. The objective of the mission is to help reduce legal backlog in courts from an average of 15 years at present to 3 years by 2012. It would also help in improving the legal environment for business. The Thirteenth Finance Commission has provided grants amounting to Rs. 5,000 crore for the States to improve the delivery of justice, including strengthening of alternate dispute resolution mechanisms.

Budget Estimates 2010-11

I now turn to the Budget Estimates for 2010-11.

112. The Gross Tax Receipts are estimated at Rs.7,46,651 crore. The Non Tax Revenue Receipts are estimated at Rs. 1,48,118 crore. The net tax revenue to the Centre as well as the expenditure provisions in 2010-11 have been estimated with reference to the recommendations of the Thirteenth Finance Commission.

113. The total expenditure proposed in the Budget Estimates for 2010-11 is Rs. 11,08,749 crore, which is an increase of 8.6 per cent over the total expenditure in BE 2009-10. The Plan and Non Plan expenditures in BE 2010-11 are estimated at Rs.3,73,092 crore and Rs.7,35,657 crore, respectively. While there is a 15 per cent increase in Plan expenditure, the increase in Non Plan expenditure is only 6 per cent over the BE of previous year. With this level of

Plan expenditure, I am confident that the total Plan expenditure would be very close to 100 per cent of the expenditure envisaged in the Eleventh Five Year Plan.

114. Honourable Members will agree that fiscal policy has to be guided by the required framework for fiscal prudence. In the Medium Term Fiscal Policy Statement presented along with Budget 2009-10, I had laid down a road map for fiscal deficit. I am happy to report that in keeping with my commitment, I have been able to present the Budget for 2010-11 with a fiscal deficit of 5.5 per cent. In the Medium Term Fiscal Policy Statement being presented to the House today, along with other Budget documents, the rolling targets for fiscal deficit are pegged at 4.8 per cent and 4.1 per cent for 2011-12 and 2012-13, respectively. These projections improve upon the recommendations of the Thirteenth Finance Commission.

115. While presenting the Budget for 2009-10, I had expressed my concern about the high level of fiscal deficit. I had also stated that the Government will address this issue in right earnest to come back to the path of fiscal consolidation at the earliest. I am happy to report that against a fiscal deficit of 7.8 per cent in 2008-09, inclusive of oil and fertiliser bonds, the comparable fiscal deficit is 6.9 per cent as per the Revised Estimates for 2009-10. Both these deficit figures are based on the revised GDP numbers published by the Central Statistical Organisation and include what were earlier referred to as below the line items. This marks an improvement of about one per cent in fiscal deficit during the current year. I have made a conscious effort to avoid issuing bonds to oil and fertiliser companies. I would like to continue with this practice of extending Government subsidy in cash, thereby bringing all subsidy related liabilities into our fiscal accounting.

116. The fiscal deficit of 5.5 per cent of GDP in 2010-11 works out to Rs. 3,81,408 crore. Taking into account the various other financing items for fiscal deficit, the actual net market borrowing of the Government in 2010-11 would be of the order of Rs. 3,45,010 crore. There will be enough space to meet the credit needs of the private sector. The Government will plan the borrowing programme in consultation with the RBI.

PART-B

Madam Speaker,

I shall now present my tax proposals.

117. While formulating them, I have been guided by the principles of sound tax administration as embodied in the following words of Kautilya:

"Thus a wise Collector General shall conduct the work of revenue collection.....in a manner that production and consumption should not be injuriously affected.....financial prosperity depends on public prosperity, abundance of harvest and prosperity of commerce among other things."

118. I had stated last year that tax reform is a process and not an event. The process I had outlined in the area of

direct taxes was to release a draft Direct Taxes Code along with a Discussion Paper. In the area of indirect taxes, the reform initiative was the introduction of a Goods and Services Tax. I have presented the developments in both reform initiatives in Part 'A' of my Speech.

119. We have continued on the path of computerisation in core areas of service delivery in the administration of direct taxes. This will reduce the physical interface between taxpayers and tax administration and speed up procedures and processes. The Centralised Processing Centre at Bengaluru is now fully functional and is processing around 20,000 returns daily. This initiative will be taken forward by setting up two more Centres during the year.

120. As a part of Government's initiative to move towards citizen centric governance, the income tax department has introduced "Sevottam", a pilot project at Pune, Kochi and Chandigarh through Aayakar Seva Kendras. These provide a single window system for registration of all applications including those for redressal of grievances as well as paper returns. This year the scheme will be extended to four more cities.

121. To achieve the roll-out of GST by April 2011, the indirect tax administrations at the Centre and the States need to revamp their internal work processes based on the use of Information Technology. I am happy to inform Honourable Members that project ACES - Automation of Central Excise & Service Tax, has already been rolled out throughout the country this year. This will impart greater transparency in tax administration and improve the delivery of taxpayer services. Similarly, a Mission Mode Project for computerisation of Commercial Taxes in States has been approved recently. With an outlay of Rs.1133 crore of which the Centre's share is Rs. 800 crore, the project will lay the foundation for the launch of GST.

122. I mentioned last year, that the income tax return forms should be simple and user friendly. The income tax department is now ready to notify SARAL-II form for individual salaried taxpayers for the coming assessment year. This form will enable individuals to enter relevant details in a simple format in only two pages.

123. To expeditiously resolve disputes with taxpayers I propose to expand the scope of cases which may be admitted by the Settlement Commission to include proceedings related to search and seizure cases pending for assessment. I also propose to expand the scope of Settlement Commission in respect of Central Excise and Customs so that certain categories of cases that hitherto fell outside its jurisdiction may be admitted.

124. Last year, amendments to the statute enabled Government to enter into tax treaties with specified territories besides sovereign states. We have commenced bi-lateral discussions to enhance the exchange of bank related and other information to effectively track tax evasion and identify undisclosed assets of resident Indians lying abroad.

Direct Taxes

I shall now deal with direct taxes.

125. Last year I provided relief to individual taxpayers by enhancing the exemption limit for all taxpayers and withdrawing the surcharge on personal income tax. Taxpayers have responded positively to these concessions by contributing a higher level of taxes. There is a persuasive case for further relief by broadening the current tax slabs which I propose as follows:

Income up to Rs. 1.6 lakh	Nil
Income above Rs. 1.6 lakh and up to Rs. 5 lakh	10 per cent
Income above Rs. 5 lakh and up to Rs. 8 lakh	20 per cent
Income above Rs. 8 lakh	30 per cent

126. The proposed broadening of tax slabs will provide substantial relief to a large number of taxpayers.

127. To promote savings as well as to ensure their utilisation for the thrust area of infrastructure, I propose to allow a deduction of an additional amount of Rs. 20,000 for investment in long-term infrastructure bonds as notified by the Central Government. This would be over and above the existing limit of Rs.1 lakh on tax savings. I am sure that these reliefs will put more money in the hands of individual taxpayers for both consumption as well as saving.

128. Besides contributions to health insurance schemes which is currently allowed as a deduction under the Income-tax Act, I propose to allow contributions to the Central Government Health Scheme also as a deduction under the same provision.

129. Taking forward my initiative of phasing out surcharge, I propose to reduce the current surcharge of 10 per cent on domestic companies to 7.5 per cent. At the same time, I propose to increase the rate of Minimum Alternate Tax (MAT) from the current rate of 15 per cent to 18 per cent of book profits. This will further promote *inter se* equity among corporate taxpayers.

130. The President, in her address to the Parliament in June 2009, had declared this decade as the Decade of Innovation. Last year, I extended the scope of weighted deduction on expenditure incurred on in-house research and development (R&D) to all manufacturing businesses except for a small negative list. To further encourage R&D across all sectors of the economy, I now propose to enhance the weighted deduction on expenditure incurred on in-house R&D from 150 per cent to 200 per cent. I also propose to enhance the weighted deduction on payments made to National Laboratories, research associations, colleges, universities and other institutions, for scientific research from 125 per cent to 175 per cent.

131. Currently, any payment made to an approved scientific research association is eligible for weighted deduction. The income of the approved scientific research association is exempt from tax. I propose that payments made to approved associations engaged in research in

social sciences or statistical research would be allowed a weighted deduction of 125 per cent. The income of such approved research associations shall be exempt from tax.

132. In my Budget Speech last year, I stated that profit linked deductions are inherently inefficient and liable to misuse. To incentivise businesses in priority sectors, I introduced investment linked deduction as an alternative to profit linked deduction. To give a boost to investment in the tourism sector which has high employment potential, I propose to extend the benefit of investment linked deduction under the Act to new hotels of two-star category and above anywhere in India.

133. To provide one time interim relief to the housing and real estate sector which was impacted by the global recession, I propose to allow pending projects to be completed within a period of five years instead of four years for claiming a deduction on their profits. I also propose to relax the norms for built-up area of shops and other commercial establishments in housing projects to enable basic facilities for their residents.

134. All businesses with a turnover exceeding Rs. 40 lakh are currently required to have their accounts audited. A similar provision also applies to all professions whose receipts exceed Rs. 10 lakh. I, as Finance Minister, had introduced these limits in my budget of 1984. It is high time to reduce the compliance burden on small taxpayers. I, therefore, propose to enhance these limits to Rs. 60 lakh in the case of businesses and Rs. 15 lakh in the case of professions.

135. To facilitate the business operations of small taxpayers, I had extended the scope of presumptive taxation to all small businesses with a turnover of up to Rs. 40 lakh. To further reduce the compliance burden on small taxpayers, I now propose to enhance this limit to Rs. 60 lakh.

136. The threshold limits of payments below which tax is not deductible at source have remained unchanged for a long time. I propose to rationalise these thresholds.

137. Relaxing the current provisions on disallowance of expenditure, I propose to allow deduction of such expenditure, if tax has been deducted at any time during the financial year and paid before the due date of filing the return. This will allow most deductors additional time up to September of the next financial year. At the same time, I propose to increase the interest charged on tax deducted but not deposited by the specified date, from 12 per cent to 18 per cent per annum.

138. Last year, I had provided for the taxation of the newly introduced Limited Liability Partnership (LLP) on the same lines as exists for a general partnership firm. To facilitate the conversion of small companies into LLPs, I propose that this will not be subject to capital gains tax.

139. Under the current provisions of the Act, "the advancement of any other object of general public utility" cannot be considered as "charitable purpose" if it involves carrying on of any activity in the nature of trade, commerce

or business. I have received representations from many organisations seeking some relaxation in this restriction. I propose that this restriction would not be applicable if the receipts from such activities do not exceed Rs. 10 lakh in the year.

140. My proposals on direct taxes are estimated to result in a revenue loss of Rs. 26,000 crore for the year.

Indirect Taxes

141. The major objectives that have guided me in the formulation of my proposals on indirect taxes are the need to achieve some degree of fiscal consolidation without impairing the recovery process and moving forward on the road to GST.

142. Unlike the time I presented the last Budget, symptoms of economic recovery are more widespread and clear-cut now. The three fiscal stimulus packages that the Government introduced in quick succession have helped the process of recovery significantly. The improvement in our economic performance encourages a course of fiscal correction even as the global situation warrants caution. Therefore, I propose to partially roll back the rate reduction in Central Excise duties and enhance the standard rate on all non-petroleum products from 8 per cent to 10 per cent *ad valorem*. The specific rates of duty applicable to portland cement and cement clinker are also being adjusted upwards proportionately. Similarly, the *ad valorem* component of excise duty on large cars, multi-utility vehicles and sports-utility vehicles which was reduced as part of the first stimulus package, is being increased by 2 percentage points to 22 per cent.

143. In the wake of spiralling petroleum prices, Government provided full exemption from basic customs duty to crude petroleum and proportionately reduced the basic duty on refined petroleum products in June, 2008. Compared to the international price of the Indian crude basket of US\$ 112 per barrel at that time, the prices are much softer at present. In view of the pressing need to move back to a fiscal consolidation path, I propose to restore the basic duty of 5 per cent on crude petroleum; 7.5 per cent on diesel and petrol and 10 per cent on other refined products. I also propose to enhance the Central Excise duty on petrol and diesel by Re. 1 per litre each.

144. Since I quit smoking many years ago, I would urge others to also follow suit, as smoking is injurious to health. To this end, I am making some structural changes in the excise duty on cigarettes, cigars and cigarillos coupled with some increase in rates. I also propose to enhance excise duty on all non-smoking tobacco such as scented tobacco, snuff, chewing tobacco etc. In addition, I propose to introduce a compounded levy scheme for chewing tobacco and branded unmanufactured tobacco based on the capacity of pouch packing machines.

145. Let me now turn to some much-needed incentives in thrust areas for sustainable growth and development.

Agriculture and Related Sectors

146. In supporting the strategy outlined for development of agriculture earlier in my speech, I propose to address a few key areas that call for focused attention. These are :

- (i) A strong supply chain for perishable farm produce to reach consumption and processing centres promptly;
- (ii) Infrastructure and technology to convert such produce into value-added products; and
- (iii) Infusion of technology to augment agricultural production.

147. Similar attention needs to be paid to related sectors such as apiary, horticulture, dairy, poultry, meat, marine and aquaculture.

148. For achieving these objectives, I propose to provide:

- project import status with a concessional import duty of 5 per cent for the setting up of mechanised handling systems and pallet racking systems in ‘mandis’ or warehouses for food grains and sugar as well as full exemption from service tax for the installation and commissioning of such equipment.
- project import status at a concessional customs duty of 5 per cent with full exemption from service tax to the initial setting up and expansion of
 - Cold storage, cold room including farm pre-coolers for preservation or storage of agriculture and related sectors produce; and
 - Processing units for such produce.
- full exemption from customs duty to refrigeration units required for the manufacture of refrigerated vans or trucks.

149. I also propose to provide:

- concessional customs duty of 5 per cent to specified agricultural machinery not manufactured in India;
- central excise exemption to specified equipment for preservation, storage and processing of agriculture and related sectors and exemption from service tax to the storage and warehousing of their produce; and
- full exemption from excise duty to trailers and semi-trailers used in agriculture.

150. Concessional import duty was provided to specified machinery for use in the plantation sector in the year 2003. This exemption is to lapse in July, 2010. The modernization of this labour-intensive sector is yet to reach the expected level. I propose therefore, to extend it up to March 31, 2011 along with a CVD exemption. I hope this will provide sufficient time for the sector to achieve the desired objective.

151. One of the prerequisites for agricultural productivity is access to good quality and disease-resistant seeds. I propose to exempt the testing and certification of agricultural seeds from service tax.

152. I also propose to exempt the transportation by road of cereals and pulses from service tax. Their transportation by rail would remain exempt.

153. I propose two measures under the Central Excise law to ease the cash flow position for small-scale manufacturers hard hit by the economic slowdown. First, they would be permitted to take full credit of Central Excise duty paid on capital goods in a single instalment in the year of their receipt. Secondly, they would be permitted to pay Central Excise duty on a quarterly, rather than monthly basis. These measures that come into effect on the April 1, 2010 should provide them considerable relief.

Environment

154. Harnessing renewable energy sources to reduce dependence on fossil fuels is now recognised as a credible strategy for combating global warming and climate change. To build the corpus of the National Clean Energy Fund announced earlier, I propose to levy a clean energy cess on coal produced in India at a nominal rate of Rs.50 per tonne. This cess will also apply to imported coal.

155. In pursuance of Government’s resolve to implement the National Solar Mission, I propose to provide a concessional customs duty of 5 per cent to machinery, instruments, equipment and appliances etc. required for the initial setting up of photo voltaic and solar thermal power generating units. I also propose to exempt them from Central Excise duty. Similarly, ground source heat pumps used to tap geo-thermal energy would be exempt from basic customs duty and special additional duty.

156. Wind energy has shown promising growth in the country in recent years. As a measure of further relief, I propose to exempt a few more specified inputs required for the manufacture of rotor blades for wind energy generators from Central Excise duty.

157. LED lights are staging a debut as a highly energy-efficient source of lighting for streets, homes and offices. Central Excise duty on these is being reduced from 8 per cent to 4 per cent at par with Compact Fluorescent Lamps.

158. Full exemption from Central Excise duty was provided to electric cars and vehicles that offer an eco-friendly alternative to petrol or diesel vehicles. The manufacturers of such vehicles have expressed difficulty in neutralising the duty paid on their inputs and components. I propose to remedy this by imposing a nominal duty of 4 per cent on such vehicles. I also propose to exempt some critical parts or sub-assemblies of such vehicles from basic customs duty and special additional duty subject to actual user condition. These parts would also enjoy a concessional CVD of 4 per cent.

159. The humble cycle rickshaw is now being acclaimed as an environment-friendly means of transport. CSIR has developed an innovative product called ‘soleckshaw’ to replace manually-operated rickshaws. It runs on batteries which are charged by solar power. I propose to provide a concessional excise duty of 4 per cent to this product. Its

key parts and components are also being exempted from customs duty.

160. To encourage the use of bio-degradable materials, I propose to exempt the import of compostable polymer from basic customs duty.

Infrastructure

161. Strengthening the public transport system is another means of reducing dependence on fossil fuels. I propose to grant project import status to 'Monorail projects for urban transport' at a concessional basic duty of 5 per cent.

162. Full exemption from import duty is available to specified machinery for road construction projects on the condition that the machinery shall not be sold or disposed of for a minimum period of five years. In view of representations that this leads to idling of machinery, I propose to allow resale of such machinery on payment of import duty at depreciated value. It is also being clarified that the importer is free to relocate such machinery to other eligible road construction projects.

163. With the subscriber base growing at 14 million per month, India is one of the fastest growing markets for mobile phone connections in the world. Domestic production of mobile phones is now picking up in view of exemptions from basic, CVD and special additional duties granted to their parts, components and accessories. To encourage the domestic manufacture of accessories, these exemptions are now being extended to parts of battery chargers and hands-free headphones. Also, the validity of the exemption from special additional duty is being extended till March 31, 2011.

Medical Sector

164. Medical equipment, instruments and appliances are subjected to a very complex import duty regime based on several long lists that describe individual items. Multiple rates coupled with descriptions not aligned with tariff lines, result in disputes and at times prevent state-of-art equipment from getting the benefit of exemption. I propose to prescribe a uniform, concessional basic duty of 5 per cent, CVD of 4 per cent with full exemption from special additional duty on all medical equipment. A concessional basic duty of 5 per cent is being prescribed on parts and accessories for the manufacture of such equipment while they would be exempt from CVD and special additional duty. Full exemption currently available to medical equipment and devices such as assistive devices, rehabilitation aids etc. is being retained. The concession available to Government hospitals or hospitals set up under a statute is also being retained.

165. The manufacturers of orthopaedic implants have represented that their inputs attract a higher rate of duty than the finished product. I propose to exempt specified inputs for the manufacture of such implants from import duty.

Infotainment

166. India is a nation of movie-goers. The film industry has been experiencing difficulties in importing digital masters of films for duplication or distribution loaded on electronic medium *vis-a-vis* those imported on cinematographic film, owing to a differential customs duty structure. I propose to rationalise this by charging customs duty only on the value of the carrier medium. The same dispensation would apply to music and gaming software imported for duplication. In keeping with the tradition of Indian cinema, however, I shall provide a surprise ending. In all such cases the value representing the transfer of intellectual rights would be subjected to service tax.

167. Cable transmission of infotainment is undergoing a transformation with the adoption of digital technology. The multi-service operators need to invest in "Digital Head End" equipment. To enable this, I propose to provide project import status at a concessional customs duty of 5 per cent with full exemption from special additional duty to the initial setting up of such projects.

Precious Metals

168. The prices of precious metals continue to rise. Since the customs duty is levied on these at specific rates, I propose to index the rates as follows:

- * On gold and platinum from Rs. 200 per 10 grams to Rs. 300 per 10 grams.
- * On silver from Rs. 1,000 per kg to Rs. 1,500 per kg.

169. Gems and jewellery is a traditional item in our export basket. Rhodium—a precious metal used for polishing jewellery attracts a basic customs duty of 10 per cent. This is being reduced to 2 per cent.

170. To encourage domestic refining capacity for gold, I propose to reduce the basic customs duty on gold ore and concentrates from 2 per cent *ad valorem* to a specific duty of Rs. 140 per 10 grams of gold content with full exemption from special additional duty. Further, the excise duty on refined gold made from such ore or concentrate is being reduced from 8 per cent to a specific duty of Rs. 280 per 10 grams.

Other Proposals

171. Full exemption from import duty is available to specified inputs or raw materials required for the manufacture of sports goods which are assuming importance as an item of export. This is being expanded to cover a few more items.

172. In order to incentivise the domestic production of microwave ovens, I propose to reduce the basic customs duty on one of its key components, namely magnetrons from 10 per cent to 5 per cent.

173. Presently, there is a value limit of Rs. 1 lakh per annum on duty-free import of commercial samples as personal baggage. I propose to enhance this limit to Rs. 3 lakh per annum.

174. Industry has represented that the exemption from special additional duty of 4 per cent based on refunds leads to substantial blockage of funds. To ease this difficulty, I propose to provide an outright exemption from special additional duty to goods imported in a pre-packaged form for retail sale. This would also cover mobile phones, watches and ready-made garments even when they are not imported in pre-packaged form. The refund-based exemption is also being retained for cases not covered by the new dispensation.

175. Toy balloons are a source of joy to millions of children. To bring a smile to their mothers' faces, I propose to fully exempt them from Central Excise duty.

176. Some of the other relief measures that I propose are as under :

- * Reduction in basic customs duty on long pepper from 70 per cent to 30 per cent;
- * Reduction in basic customs duty on asafoetida from 30 per cent to 20 per cent;
- * Reduction in central excise duty on replaceable kits for household type water filters other than those based on RO technology to 4 per cent;
- * Reduction in central excise duty on corrugated boxes and cartons from 8 per cent to 4 per cent;
- * Reduction in central excise duty on latex rubber thread from 8 per cent to 4 per cent; and
- * Reduction in excise duty on goods covered under the Medicinal and Toilet Preparations Act from 16 per cent to 10 per cent.

177. My proposals relating to customs and central excise are estimated to result in a net revenue gain of Rs. 43,500 crore for the year.

Service Tax

178. The service sector contributes nearly 60 per cent of the GDP. The service tax to GDP ratio however, is only around 1 per cent. This sector thus, has significant potential to augment revenue.

179. To bridge this gap, I had the option to raise the rate of service tax to 12 per cent as it was before I introduced the third stimulus package. I am not resorting to this option to maintain the growth momentum and also to bring about a convergence in the rates of tax on goods and services. I, therefore, propose to retain the rate of tax on services at 10 per cent to pave the way forward for GST.

180. I had another option—to bring all services under service tax. I am not opting for this either at this stage. I propose, however, to bring certain services, hitherto

untaxed, within the purview of the service tax levy. These are being notified separately.

181. I am also proposing certain legislative changes to plug revenue leakages, to remove distortions and to clarify certain doubts that have arisen over a period of time. I do not want to waste the precious time of the House elaborating the details, as they are available in the Finance Bill and other Budget documents.

182. Export of services, especially in the area of Information Technology and Business Process Outsourcing, generates substantial employment and brings in foreign exchange. I propose to ease the process of refund of accumulated credit to exporters of services by making necessary changes in the definition of export of services and procedures.

183. Accredited news agencies which provide news feed online attract service tax. Acknowledging the yeoman services of such news agencies in disseminating news, I propose to exempt such news agencies that meet certain criteria, from service tax.

184. My proposals relating to service tax are estimated to result in a net revenue gain of Rs. 3,000 crore for the year.

185. Copies of notifications giving effect to the changes in customs, central excise and service tax will be laid on the Table of the House in due course.

186. My proposals on Direct Taxes are estimated to result in a revenue loss of Rs. 26,000 crore for the year. Proposals relating to Indirect Taxes are estimated to result in a net revenue gain of Rs. 46,500 crore for the year. Taking into account the concessions being given in my tax proposals and measures taken to mobilise additional resources, the net revenue gain is estimated to be Rs. 20,500 crore for the year.

187. We have emerged from the global slowdown faster than any other nation. I did not hesitate in exercising my judgement on the course of action last year and I have no hesitation in my mind now. Our actions today will determine our tomorrow.

188. This Budget belongs to 'Aam Aadmi'. It belongs to the farmer, the agriculturist, the entrepreneur and the investor. The opportunity is great. The time is right. I have placed my faith in the hands of the people who, I know, can be depended upon to rise to any occasion in national interest. I have placed my faith in the collective conscience of the nation that can be touched to scale undreamt of heights in the coming years.

189. Madam Speaker, with these words I commend the Budget to the House."

SHAKTIKANTA DAS, Jt. Secy. (Budget)